शर्मा हार्डওয়্যার
SHARMA HARDWARE
Sharma Gali, SJ Road
Athgaon, Guwahati-01
98648-02947

E-Paper : www.goodluckpublications.com, • www.vbslive.in
हिंदी दैनिक
गुवाहाटी, नई दिल्ली, शिमला और जम्मू से एकसाथ प्रकाशित
राष्ट्र निर्माण में प्रयत्नशील

विकसित भारत समाचार

वर्ष : 12 | अंक : 267 | गुवाहाटी | सोमवार, 4 मई, 2026 | मूल्य : 10 रुपए | पृष्ठ : 8 | VIKSIT BHARAT SAMACHAR | Regd. RNI No. ASSHIN/2014/56526

जाजपुर में 58 लोग अस्पताल में भर्ती, एक की गई जान पेज 2
मिजोरम : फर्जी अदालती आदेशों का इस्तेमाल करके 16 दोषियों की ... पेज 3
हरियाणा के मुख्यमंत्री की पंजाब में ओबीसी को एकजुटता की अपील... पेज 5
वैभव को योग्यता के आधार पर आंकना चाहिए, न कि उम्र से पेज 7

door graph Premium Quality Hinges
S.S. Traders
Suppliers in : All kinds of Door Fittings Modular Kitchen & Accessories, etc.
D. Neog Path, Near Dona Planet ABC, G.S. Road, Guwahati - 05
97079-99344

सुप्रभात

मुश्किलों के बाद हासिल की हुई सफलता ही असली आनंद देती है।

– **अब्दुल कलाम**

पांच राज्यों के विस चुनाव परिणाम आज

गुवाहाटी/नई दिल्ली/कोलकाता/चेन्नई। असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में सोमवार को वोटों की गिनती होगी। एक रोमांचक और हाई-वोल्टेज मुकाबले के बाद, यह परिणाम टीएमसी और डीएमके जैसी प्रमुख सत्तारूढ़ क्षेत्रीय पार्टियों के साथ-साथ भाजपा, कांग्रेस और वामपंथी दलों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। मतगणना केंद्रों पर सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से मतदान प्रक्रिया शुरू होगी, जहां तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था होगी। पहली बार, चुनाव आयोग ने मतगणना केंद्रों में अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए ईसीआईएनईटी के माध्यम से क्यूआर कोड आधारित फोटो पहचान पत्र प्रणाली शुरू की है। भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए असम में हैट्रिक की उम्मीद कर रहा है। राज्य की 126 विधानसभा सीटों से 722 उम्मीदवारों के चुनावी नतीजों का जिम्मा संभालने वाली ईवीएम को 35 जिलों के 40 मतगणना केंद्रों पर खोला जाएगा। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की पच्चीस कंपनियों को, जिनमें प्रत्येक में लगभग 100 जवान हैं, मतगणना केंद्रों और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) वाले सुरक्षित कक्षों की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि सीएपीएफ की दो अतिरिक्त कंपनियों को स्थायी ड्यूटी पर रखा जाएगा, जबकि राज्य सशस्त्र पुलिस की 93 कंपनियों को जिलों में तैनात किया गया है। राज्य में 9 अप्रैल को मतदान हुआ था, जिसमें 85.96 प्रतिशत मतदान हुआ था। 722 उम्मीदवारों में से कांग्रेस ने सबसे अधिक 99 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, उसके बाद भाजपा ने 90, एआईयूडीएफ ने 30, एनडीए सहयोगी असम गण परिषद (अगप) ने 26 और बोडो पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) ने 11 उम्मीदवार उतारे हैं। विपक्षी गठबंधन में रायजोर दल ने 13 सीटों पर, असम जातीय परिषद ने 10 सीटों पर, सीपीआई (एम) ने तीन सीटों पर और सर्वदलीय पहाड़ी नेता सम्मेलन ने दो सीटों पर चुनाव लड़ा। प्रमुख उम्मीदवारों में भाजपा के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा, कांग्रेस की प्रदेश इकाई के प्रमुख गौरव गोगोई, विधानसभा अध्यक्ष विश्वजीत दैमारी और रायजोर दल के प्रमुख और सांसद अखिल गोगोई शामिल हैं। उधर पश्चिम बंगाल में 293 विधानसभा सीटों के लिए 77 केंद्रों पर वोटों की गिनती की जाएगी, जहां इस बार अभूतपूर्व सुरक्षा तैनाती देखी गई है और परिणाम दिवस से पहले का माहौल कटुतापूर्ण है, जिसमें सत्तारूढ़ टीएमसी और विपक्षी भाजपा दोनों ने वोट में हेरफेर की आशंका व्यक्त की है। राज्य में दो चरणों में हुए चुनाव 29 अप्रैल को समाप्त हुए, जिसमें आजादी के बाद से अब तक का सबसे अधिक 92.47 प्रतिशत मतदान हुआ। दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा नामक एक निर्वाचन क्षेत्र में *गंभीर चुनावी अपराधों* के कारण चुनाव रद्द कर दिया गया और वहां 21 मई को नए सिरे से चुनाव होंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) मुख्य विपक्षी दल भाजपा की कड़ी चुनौती का सामना करते हुए लगातार चौथी बार सत्ता में आने की उम्मीद कर रही है, वहीं सीपीआई (एम) और कांग्रेस 2021 के चुनावों में मिली करारी हार के बाद अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश कर रही हैं। हुमायूं कबीर की एजेयूपी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम जैसी छोटी पार्टियां भी कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। चुनाव आयोग ने इस वर्ष मतगणना केंद्रों की संख्या को पहले घोषित 87 से घटाकर 77 कर दिया है, जबकि 2021 में यह संख्या 108 थी। साथ ही, आयोग ने बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था भी लागू की है। चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मतगणना शांतिपूर्ण, पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चुनाव आयोग ने 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों को तैनात किया है। इसने मतगणना केंद्रों पर सख्त प्रवेश नियंत्रण उपाय लागू किए हैं, जिनमें मतगणना अधिकारियों और पर्यवेक्षकों को छोड़कर सभी के लिए मोबाइल फोन पर प्रतिबंध शामिल है। वहीं केरल में, 2024 के लोकसभा चुनावों और हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में अपने प्रदर्शन से उत्साहित कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ, दो कार्यकालों से सत्ता में रहे वाम लोकतांत्रिक मोर्चे (एलडीएफ) को सत्ता से बाहर करने की उम्मीद कर रहा है, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए अपनी द्विध्रुवीय राजनीति के साथ राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। एलडीएफ की हार से 1960 के दशक के बाद पहली बार ऐसा होगा कि किसी भी भारतीय राज्य में वामपंथी दल सत्ता में नहीं होंगे। राज्य में 140 सीटों के लिए कुल 883 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। 43 स्थानों पर 140 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि इस अभ्यास के लिए 15,464 कर्मियों को तैनात किया गया है, जिनमें 140 रिटर्निंग ऑफिसर, 1,340 अतिरिक्त रिटर्निंग ऑफिसर, 4,208 माइक्रो ऑब्जर्वर, 4,208 काउंटिंग सुपरवाइजर और 5,563 काउंटिंग असिस्टेंट शामिल हैं। मतगणना केंद्रों की सुरक्षा के लिए राज्य पुलिस कर्मियों के साथ केंद्रीय बलों की 25 कंपनियां तैनात की गई हैं। हालांकि भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए सरकार बनाने की दौड़ में नहीं है, लेकिन वह इस चुनाव को केरल में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण मानता है, क्योंकि वह 2021 में कोई भी सीट जीतने में विफल रहा था। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके एक बदले हुए राजनीतिक परिदृश्य में चुनाव लड़ने के बाद लगातार दूसरी बार सत्ता में आने की उम्मीद कर रही है, क्योंकि उसके मुख्य प्रतिद्वंद्वी एआईएडीएमके के अलावा, अभिनेता-राजनेता विजय के नेतृत्व वाली टीवीके और तमिल राष्ट्रवादी सीमान की एनटीके जैसी नई पार्टियां भी सत्ता में आ गई हैं। तमिलनाडु की मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक ने कहा कि राज्य भर में नामित 62 मतगणना केंद्रों पर 4 मई को होने वाली मतगणना के लिए एक व्यापक त्रिस्तरीय सुरक्षा योजना सहित सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। मतगणना कार्य में लगे अधिकारियों -शेष पृष्ठ दो पर

न्यूज गैलरी

इंफाल एयरपोर्ट कार्गो टर्मिनल के पास विस्फोट

इंफाल (हि.स.)। मणिपुर में इंफाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल के पास बम विस्फोट की खबर सामने आई है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही मौके पर फॉरेंसिक टीम पहुंचकर जांच आरंभ किया। शुरुआती जानकारी के आधार पर, मणिपुर पुलिस के एक सूत्र ने बताया कि रविवार -शेष पृष्ठ दो पर

त्रिपुरा में 70 वर्षीय दादा पर नाबालिग से दुष्कर्म हत्या का आरोप, गिरफ्तार

अगरतला। त्रिपुरा के सोनामुरा इलाके में एक नाबालिग बच्ची की संदिग्ध मौत के मामले ने सनसनी फैला दी है। पुलिस ने इस मामले में 70 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिस पर दुष्कर्म और हत्या जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पुलिस के अनुसार, 29 अप्रैल को सूचना मिली थी कि एक नाबालिग बच्ची की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। शुरुआती जांच में -शेष पृष्ठ दो पर

पवन खेड़ा का दिल्ली में भव्य स्वागत, बोले-

संविधान जीता, दमनकारी मशीनरी हारी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का दिल्ली में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने संविधान और न्यायपालिका के प्रति अपना अटूट विश्वास दोहराया। यह पूरा मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की पत्नी से जुड़े कथित मानहानि और जालसाजी के आरोपों से संबंधित है, जिसमें कोर्ट ने खेड़ा को बड़ी राहत दी है। अग्रिम जमानत मिलने के बाद जब पवन खेड़ा दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, तो वहां बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। जयराम रमेश समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने इस फैसले को *संविधान की जीत* बताया। खेड़ा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब भी सरकार अपनी मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर किसी नागरिक के अधिकारों को दबाने की कोशिश करती है, तब बाबा साहब का बनाया संविधान ही रक्षा कवच बनकर सामने आता है। जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की -शेष पृष्ठ दो पर

ग्रेट निकोबार परियोजना पर कांग्रेस ने फिर उठाए सवाल

नई दिल्ली (हि.स.)। कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने ग्रेट निकोबार द्वीप विकास परियोजना को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे जुड़े पर्यावरणीय, सामाजिक और पारदर्शिता संबंधी मुद्दों पर सरकार जवाब देने से बच रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि 28 अप्रैल को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ग्रेट निकोबार यात्रा के बाद सरकार ने प्रेस बयान जारी कर ध्यान भटकाने का प्रयास किया। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया -शेष पृष्ठ दो पर

ममता के निर्वाचन क्षेत्र में स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामा

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के मतगणना केंद्र के बाहर रविवार को हंगामा हुआ। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा के झंडे वाले दो वाहनों को उस परिसर में प्रवेश दिया गया, जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) रखी गई हैं। यह घटना उस समय हुई, जब इससे एक दिन पहले ममता बनर्जी ने सखावत बालिका विद्यालय में स्थित इस मतगणना केंद्र के बाहर चार घंटे तक धरना दिया। उन्होंने स्ट्रांग रूम में अनधिकृतिक लोगों के के प्रवेश का आरोप लगाया था। मतदान खत्म होने के बाद अब पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच सत्ता को लेकर तनाव बढ़ गया है। दोनों दलों के नेता और कार्यकर्ता राज्यभर में स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पर नजर रखे हुए हैं, जहां उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद है। भारी जीत का भरोसा -शेष पृष्ठ दो पर

आधार कार्ड के स्वरूप में बदलाव की खबरों को सरकार ने बताया भ्रामक

नई दिल्ली (हि.स.)। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आधार कार्ड के स्वरूप में बदलाव से जुड़ी खबरों को खारिज करते हुए बताया कि इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है। मंत्रालय के अनुसार, हाल ही में कुछ समाचार माध्यमों और सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर ऐसी खबरें प्रसारित हो रही हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि वर्ष के अंत तक आधार कार्ड को केवल फोटो और क्यूआर कोड तक सीमित कर दिया जाएगा। मंत्रालय ने इन दावों को पूरी तरह गलत बताया है। मंत्रालय ने कहा कि इस तरह के किसी भी बदलाव की कोई योजना नहीं है और इस संबंध में फैल रही खबरें भ्रामक हैं, जो लोगों -शेष पृष्ठ दो पर

मिशन से कमीशन की ओर बढ़ी पत्रकारिता

समाज का विश्वास कायम रखना सबसे बड़ी चुनौती : जितेंद्र तिवारी

वाराणसी (हि.स.)। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गांधी अध्ययन पीठ सभागार में विश्व संवाद केंद्र वाराणसी की ओर से आयोजित देवर्षि नारद जयंती संगोष्ठी एवं पत्रकार सम्मान समारोह में मीडिया की बदलती दिशा, उसकी विश्वसनीयता और समाज के प्रति जिम्मेदारी जैसे अहम विषयों पर काशी में गंभीर मंथन हुआ। *पंच परिवर्तन : समाज एवं मीडिया* विषय पर हिन्दुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी के संपादक जितेंद्र तिवारी ने पत्रकारिता के मूल स्वरूप और वर्तमान चुनौतियों पर बेबाक टिप्पणी की और आज के दौर में मीडिया पर समाज के विश्वास को कायम रखने को सबसे बड़ी चुनौती बताया। न्यूज एजेंसी के संपादक जितेंद्र तिवारी ने कहा कि पत्रकारिता की शुरुआत एक मिशन के रूप में हुई थी, जिसका -शेष पृष्ठ दो पर

विवेक विहार में चारमंजिला रिहायशी इमारत बनी लाक्षागृह, नौ की मौत

नई दिल्ली (हि.स.)। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विवेक विहार में आज तड़के चारमंजिला रिहायशी इमारत में आग लग गई। इस हादसे में नौ लोगों की मौत हो गई। कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। दो लोग मामूली रूप से झुलस गए हैं। उन्हें गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक, तड़के करीब 3:48 बजे विवेक विहार थाना को एक पीसीआर कॉल के माध्यम से आग लगने की सूचना मिली। पुलिस और दमकल विभाग के अलावा अन्य टीमें तत्काल घटनास्थल (विवेक विहार फेज-1 स्थित मकान नंबर बी-13) पर पहुंचे। दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल पर ऊंची लपटें उठ -शेष पृष्ठ दो पर

विदेशी आक्रमणों के बावजूद आदिवासियों ने बचाई देश की आत्मा : भागवत

नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भगवत ने कहा कि विदेशी आक्रमणों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद आदिवासी और अनुसूचित जाति समुदायों ने भारत की पहचान और आत्मा को संरक्षित रखा। भागवत ने जोर देकर कहा कि इन समुदायों के योगदान को पहचानते हुए उन्हें मुख्यधारा के विकास में पूरी तरह शामिल करना जरूरी है। दरअसल मोहन भागवत शनिवार को मुंबई में कर्मयोगी पुरस्कार समारोह में शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि मानव जीवन का उद्देश्य समाज को कुछ वापस देना है। उन्होंने कहा कि -शेष पृष्ठ दो पर

चुनाव आयोग का बड़ा फैसला

बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर 21 मई को फिर से वोटिंग

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा सीट पर मतदान के दौरान गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला किया है। चुनाव आयोग ने फलता विधानसभा सीट पर 29 अप्रैल को हुए मतदान स्थगित करने की घोषणा की है। चुनाव आयोग ने अलग से इस सीट के सभी पोलिंग बूथों पर 21 मई को फिर से मतदान कराने का एलान किया है और 24 मई को इस सीट पर वोटों की गिनती होगी। चुनाव आयोग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 29 अप्रैल 2026 को फलता विधानसभा क्षेत्र, पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में पोलिंग स्टेशनों पर मतदान के दौरान गंभीर चुनावी अपराधों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दखलंदाजी की घटना घटी थी। चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि इसके मद्देनजर सहायक -शेष पृष्ठ दो पर

ईरान ने अमेरिका को भेजा नया शांति प्रस्ताव राष्ट्रपति ट्रंप को नहीं लगता बनेगी बात

वाशिंगटन/दोहा/तेहरान (हि.स.)। ईरान ने अमेरिका को नया शांति प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव 14 सूत्रीय है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार किया है कि यह प्रस्ताव मिल चुका है। उन्होंने शनिवार को पाम बीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर पत्रकारों को यह जानकारी दी। ट्रंप ने साफ किया कि उन्होंने अभी भी नहीं लग रहा कि ईरान से बात बन पाएगी। उन्होंने कहा कि वह शांति प्रस्ताव की गहराई से समीक्षा करेंगे। इस बीच अमेरिका-इजराइल के फरवरी के आखिर में किए गए सैन्य हमले के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य में संकट लगातार गहरा रहा है। कतर के प्रधानमंत्री ने ईरान के विदेशमंत्री से सूझबूझ से काम लेने की सलाह दी है। सीबीएस न्यूज, फॉक्स न्यूज, अल जजीरा और तसनीम की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप ने पत्रकारों को बताया कि ईरान ने अभी-अभी प्रस्ताव भेजा है। बावजूद इसके उन्हें नहीं लगता कि ईरान समझौता कर पाएगा। इसमें आक्रमण न करने की गारंटी, नाकाबंदी हटाने और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त -शेष पृष्ठ दो पर

CLASSIFIED

For all kinds of classified advertisements please contact

97070-14771
86382-00107

मणिपुर में बम हमले के शिकार दो मासूमों का 25 दिन बाद अंतिम संस्कार

इंफाल। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में ट्रोंग्लाओबी घटना में जान गंवाने वाले दो मासूम बच्चों का अंतिम संस्कार 25 दिन बाद किया गया। इस घटना ने पूरे इलाके को गहरे शोक में डाल दिया है। जानकारी के अनुसार, 7 अप्रैल को मोइरांग के ट्रोंग्लाओबी अवांग लीकेई इलाके में स्थित एक घर पर संदिग्ध उग्रवादियों द्वारा बम फेंका गया था। इस हमले में दो बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि उनकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। लंबे समय तक चले हालात और प्रक्रियाओं के बाद, अब जाकर दोनों बच्चों का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के दौरान इलाके में माहौल बेहद गमगीन रहा और लोगों ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। यह घटना अब भी स्थानीय लोगों के बीच डर और आक्रोश का कारण बनी हुई है, जबकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

ओडिशा : दहीबड़ा बना जहर...

जाजपुर में 58 लोग अस्पताल में भर्ती, एक की गई जान

जाजपुर। ओडिशा के जाजपुर में खराब *दही बड़ा* खाने से कम से कम 58 लोग बीमार पड़ गए। यहीं पर एक बुजुर्ग महिला की मौत भी हो गई। ये घटना दशरथपुर ब्लॉक के *पाटा पुर* नाम के एक गांव में हुई। यहां शुक्रवार सुबह करीब 8.30 बजे से 9.30 बजे के बीच गांव वालों ने सड़क किनारे एक विक्रेता से दही बड़ा खाया था। नाश्ते में पसंद किए जाने वाले दही बड़ा खाने के कुछ ही देर बाद, कई लोगों को उल्टी और दस्त जैसे लक्षण महसूस होने लगे। परिवार के सदस्यों ने तुरंत उन्हें इलाज के लिए पास के सरकारी अस्पतालों में पहुंचाया। हालांकि, जब उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ तो उनमें से 52 लोगों को एम्बुलेंस से जाजपुर के जिला मुख्यालय अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। प्रभावित लोगों में बच्चे और बड़े, दोनों शामिल हैं। जाजपुर के सीडीएमओ के मुताबिक, 25 बच्चे हैं और 27 बड़े हैं। बाकी 6 लोगों का इलाज उनके गांव में ही चल रहा है। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग और जाजपुर के सांसद डॉ. रबिंद्र कुमार बेहरा हॉस्पिटल पहुंचे। यहां पर उन्होंने मरीजों से बातचीत की और उनकी सेहत का हालचाल पूछा। उन्होंने इस घटना के बारे में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ चर्चा भी की। स्वास्थ्य अधिकारियों ने खाने से जहर फैलने के इस संदिग्ध मामले की जांच शुरू कर दी है। आगे की जानकारी का इंतजार है। मीडिया से बातचीत के दौरान जाजपुर के सीडीएमओ डॉ. बिजय कुमार मिश्रा ने बताया कि सभी मरीजो की हालत अब स्थिर है। कुछ लोगों को हल्का बुखार है, जो बाद में ठीक हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुझे कैजुअल्टी डिपार्टमेंट के साथ-साथ मंगलपुर सीएचसी के हमारे फील्ड स्टाफ से भी जानकारी मिली कि पटपुर गांव के कुछ लोग लूज मोशन, पेट दर्द और उल्टी से परेशान हैं। कल सुबह 8:00 से 11:00 बजे के बीच कुछ दही बड़ा और कुछ करी खाने की बात सामने आई है। वहीं कुछ लोगों में शाम को और बाकियों में रात को लक्षण दिखने शुरू हो गए। उन्होंने बताया कि एक मरीज रुद्र नारायण जेना ने बताया कि दोपहर करीब 12:00 बजे लक्षण दिखने शुरू हुए, जब उन्हें उल्टी और दस्त होने लगे।

बंगाल चुनाव : फालता में पुनर्मतदान पर भड़के अभिषेक, भाजपा को दी चुनौती

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने फालता विधानसभा क्षेत्र में दोबारा चुनाव कराने के फैसले पर भाजपा नेता अमित मालवीय को कड़ा जवाब दिया है। मालवीय ने तंज कसते हुए कहा था कि *डायमंड हार्बर मॉडल* पूरी तरह फेल हो गया है। इसके जवाब में अभिषेक बनर्जी ने भाजपा को चुनौती देते हुए इसे *बांग्ला विरोधी गुजराती गिरोह* की साजिश बताया। अभिषेक बनर्जी ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उनके विरोधी चाहे 10 जन्म भी ले लें, तो भी डायमंड हार्बर मॉडल का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उन्होंने सीधे तौर पर चुनौती देते हुए कहा कि पूरी ताकत लगा लीजिए। मैं भारत सरकार को चुनौती देता हूं कि वे फालता आएं और अपने सबसे मजबूत उम्मीदवार या दिल्ली से किसी बड़े नेता को चुनाव लड़ने के लिए भेजें। अगर हिम्मत है, तो फालता में मुकाबला करके दिखाएं। यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब भाजपा नेता अमित मालवीय ने चुनाव आयोग के पुनर्मतदान वाले फैसले पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि फालता के सभी 285 बूथों पर दोबारा वोटिंग का आदेश साबित करता है कि डायमंड हार्बर मॉडल धराशायी हो चुका है। बता दें कि फालता विधानसभा क्षेत्र डायमंड हार्बर लोकसभा के अंतर्गत आता है, जहां से अभिषेक बनर्जी सांसद हैं। अब इस सीट पर 21 मई को दोबारा वोट डाले जाएंगे और 24 मई को नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग ने यह फैसला 29 अप्रैल को हुई वोटिंग के दौरान मिली गंभीर शिकायतों के बाद लिया है। दक्षिण 24 परगना के फालता इलाके में स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया था कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें डराया और धमकाया है। लोगों ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर करते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया था। इन्हीं शिकायतों को आधार बनाकर आयोग ने चुनाव में धांधली की बात मानी और दोबारा मतदान का आदेश दिया। इससे पहले जिले के 15 मतदान केंद्रों पर हुए पुनर्मतदान में करीब 90 प्रतिशत वोटिंग हुई थी, जो काफी हैरान करने वाली थी। अमित मालवीय ने आरोप लगाया था कि दूसरे चरण के दौरान मतदाताओं को अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनने से रोका गया। इन्ही आरोपों और जमीनी रिपोर्ट के बाद चुनाव आयोग ने फालता सीट पर पूरी तरह से फिर से चुनाव कराने का निर्देश जारी किया है।

खारूपेटिया में जीजा ने की साले की हत्या

दरंग (हिंस)। दरंग जिले के खारूपेटिया क्षेत्र में एक सनसनीखेज हत्या की घटना सामने आई है। 3 नंबर आरिमारी शांति बाजार में हुई इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। रविवार को मिली जानकारी के अनुसार, मोहम्मद अली ने चाकू से वार कर अपने साले आक्काश अली की हत्या कर दी। हमले में गंभीर रूप से घायल आक्कास अली की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी मोहम्मद अली फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश में अभियान चला रही है। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि यह हत्याकांड प्रेम प्रसंग के कारण हुआ है। हालांकि, मामले की वास्तविक वजह जानने के लिए पुलिस द्वारा विस्तृत जांच जारी है। उधर जोनाई क्षेत्र में पुलिस ने एक अवैध शिकारी को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आज बताया कि पकड़े गए आरोपी की पहचान ऊपरी चिरोंग गांव के नरेन पेगू के रूप में हुई है।

राजस्थान के कई जिलों में आंधी-बारिश का कहर : जयपुर, टोंक और अजमेर में तीन मौते

जयपुर (हिंस)। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से आंधी-बारिश का दौर लगातार जारी है। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में शनिवार देर शाम तेज अंधड़, धूलभरी हवाओं और बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया। जयपुर, टोंक और अजमेर में मौसम जनित हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दौसा में आगजनी और मकान ढहने जैसी घटनाओं में कई लोग घायल हुए हैं। मौसम विभाग ने रविवार को 11 जिलों में आंधी-बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है, जबकि 4 मई को 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। जयपुर में शनिवार देर शाम करीब डेढ़ घंटे तक तेज तूफानी बारिश हुई। इस दौरान 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं, जिससे कई स्थानों पर पेड़ और बिजली लाइनें क्षतिग्रस्त हो गईं। जयसिंहपुरा खोर क्षेत्र में अंधड़ के दौरान हाईटेंशन लाइन टूटकर सड़क पर गिर गई, लेकिन बिजली सप्लाई बंद नहीं होने से बाइक सवार युवक यूनुस इसकी चपेट में आ गया और जिंदा जल गया। प्रत्यक्षदर्शी करंट के डर से उसकी मदद नहीं कर सके। टोंक जिले के दूनी क्षेत्र में तेज अंधड़ के दौरान पेड़ के नीचे बंधी बकरी को खोलने गए वृद्ध मिश्रीलाल मीणा पर पेड़ की भारी टहनी गिर गई, जिससे उनकी मौत हो गई। वहीं अजमेर में खराब मौसम के बीच मकान ढहने से दो महिलाएं मलबे में दब गईं, जिनमें से एक महिला की मौत हो गई जबकि दूसरी घायल हो गई। दौसा जिले में भी तूफान ने भारी तबाही मचाई। महवा क्षेत्र के सालिमपुर गांव में तेज आंधी के दौरान एक कच्चे घर में आग लग गई, जिसमें 18 बकरियां जिंदा जल गईं। आग बुझाने के प्रयास में परिवार के चार सदस्य गंभीर रूप से झुलस गए। सिकंदरा क्षेत्र के बुड़ली गांव में टीनशेड की दीवार गिरने से एक महिला घायल हो गई और कई मवेशी दब गए, जिनमें एक भैंस की मौत हो गई। प्रदेश के बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनूं, अलवर, अजमेर और कोटा सहित कई जिलों में भी शनिवार को धूलभरी हवाओं के साथ बारिश हुई। कई क्षेत्रों में पेड़ उखड़ गए, बिजली आपूर्ति बाधित रही और तापमान में उल्लेखनीय गिरावट हुई। जयपुर में पिछले पांच दिनों में तापमान करीब 5 डिग्री तक गिर गया है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, फलोदी और बाड़मेर जैसे जिलों में शनिवार को भी गर्मी का प्रकोप जारी रहा, जहां अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। जैसलमेर और फलोदी में तापमान 44.4 डिग्री, जबकि बाड़मेर में 44.3 डिग्री सेल्सियस मापा गया। मौसम विभाग के अनुसार आगामी तीन दिनों तक राजस्थान में आंधी-बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। 4 मई को जयपुर, बीकानेर, भरतपुर और अजमेर संभाग के कई जिलों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से अंधड़ चलने की संभावना है। इससे अगले एक सप्ताह तक हीटवेव से राहत मिलने की उम्मीद है।

पृष्ठ एक का शेष

पांच राज्यों के ...

और सूक्ष्म पर्यवेक्षकों तथा पुलिस कर्मियों सहित लगभग 1.25 लाख कर्मियों को तैनात किया गया है। ईवीएम के लिए कुल 234 मतगणना कक्षों की व्यवस्था की गई है। डाक मतपत्रों और इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे गए डाक मतपत्रों (ईटीपीबी) की गिनती के लिए अतिरिक्त 240 कक्ष निर्धारित किए गए हैं। मतगणना कार्य के लिए कुल 10,545 मतगणना कर्मियों को तैनात किया गया है, जिन्हें 4,624 सूक्ष्म पर्यवेक्षकों का सहयोग प्राप्त है। चुनाव आयोग ने मतगणना की प्रक्रिया की निगरानी के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक-एक करके कुल 234 मतगणना पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया है। वहीं पुडुचेरी में केंद्र शासित प्रदेश भर में छह मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। एआईएनआरसी, भाजपा, एआईएडीएमके और एलजेके से मिलकर बने एनडीए को कांग्रेस, डीएमके और वीसीके से मिलकर बने इंडिया ब्लॉक से चुनौती मिल रही है। गोवा, कर्नाटक, नागालैंड, गुजरात और महाराष्ट्र की आठ सीटों पर भी वोटों की गिनती होगी, जहां पिछले महीने मौजूदा विधायकों की मृत्यु के बाद उपचुनाव हुए थे। आठ निर्वाचन क्षेत्र हैं गोवा में पोंडा, कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे दक्षिण, नागालैंड में कोरीडांग, त्रिपुरा में धर्मनगर, गुजरात में उमरेठ और महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती।

संविधान जीता, दमनकारी...

बेंच ने सुनवाई के दौरान अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में यह मामला *राजनीति से प्रेरित* और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से प्रभावित लगता है। अदालत ने माना कि इस मामले में हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने गौहाटी हाई कोर्ट के उस फैसले को भी त्रुटिपूर्ण बताया, जिसमें खेड़ा की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को जांच में पूरा सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। जमानत की मुख्य शर्तों में, पुलिस जब भी बुलाएगी, उन्हें जांच के लिए पेश होना होगा। वे गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे और बिना अदालत की अनुमति के वे देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकेंगे, शामिल हैं। यह मामला पवन खेड़ा द्वारा एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान असम के मुख्यमंत्री की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा पर लगाए गए आरोपों से जुड़ा है। उन पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर मानहानि और जालसाजी की। हालांकि, पवन खेड़ा ने कहा कि यह फैसला सिर्फ उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं है, बल्कि देश के उन सभी लोगों के लिए संदेश है जो दमनकारी कदमों के खिलाफ खड़े हैं।

ग्रेट निकोबार परियोजना ...

प्लेटफार्म एक्स पर जारी विस्तृत बयान में कहा कि सरकार द्वारा 01 मई को जारी प्रेस नोट में उन गंभीर चिंताओं का समाधान नहीं किया गया है, जो पहले से ही स्थानीय समुदायों, पर्यावरणविदों, मानवविज्ञानियों और विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा उठाई जा चुकी हैं। इन मुद्दों को लेकर उन्होंने स्वयं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री को सितंबर 2024 में पत्र लिखकर अवगत कराया था। रमेश ने कहा कि यह द्वीप जैव विविधता के दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील और विशिष्ट है। पिछले पांच वर्षों में यहां लगभग 50 नई प्रजातियों की पहचान की गई है, जिनमें पक्षी, सरीसृप और समुद्री जीव शामिल हैं। प्रस्तावित परियोजना स्थल गैलाथिया खाड़ी तटीय विनियमन क्षेत्र-1ए के अंतर्गत आता है, जहां बंदरगाह निर्माण की अनुमति नहीं होती। इस क्षेत्र में 20,000 से अधिक प्रवाल संरचनाएं मौजूद हैं और यह उत्तरी हिंद महासागर में विशाल लेदरबैक कछुओं के प्रजनन का प्रमुख स्थल माना जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रिया में शामिल संस्थानों की भूमिका पर भी प्रश्न उठते हैं। वन्यजीव संस्थान और प्राणी सर्वेक्षण जैसे संस्थानों को परियोजना से जुड़े अध्ययन और निगरानी कार्य दिए गए, जबकि इन्हीं संस्थानों की भूमिका मंजूरी प्रक्रिया में भी रही है, जिससे हितों के टकराव की स्थिति बनती है। कुछ स्वतंत्र संस्थानों को, जिन्होंने परियोजना पर आलोचनात्मक रुख अपनाया था, उन्हें प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया।

ममता के निर्वाचन...

जताने के बावजूद ममता बनर्जी ने कई बार मतगणना में गड़बड़ी और ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंका जताई है। रविवार सुबह टीएमसी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा के झंडे लगी दो गाड़ियां परिसर में घुसीं और स्ट्रांग रूम के पास तक पहुंच गईं। एक कार्यकर्ता ने कहा कि बिना पहचान पत्र के किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। फिर भी इन वाहनों को कैसे प्रवेश मिला। टीएमसी ने दावा किया कि पुलिस ने वाहनों को हटाने का भरोसा दिया। लेकिन वह कुछ समय तक वहां खड़े रहे। हालांकि, निर्वाचन आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वाहन पास की सड़क से गुजर रहा था और जांच के बाद उसे जाने दिया गया, क्योंकि उसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। इससे पहले गुरुवार रात कोलकाता के दो मतगणना केंद्रों पर भी हंगामा हुआ था। टीएमसी नेताओं ने स्ट्रांग रूम में पारदर्शिता की कमी और गड़बड़ी की आशंका जताई थी। हावड़ा और अन्य जगहों पर भी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और सीसीटीवी बंद होने के आरोप लगाए। चुनाव आयोग ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि निगरानी कैमरे लगातार काम कर रहे थे। वहीं, भाजपा के प्रवक्ता सजल घोष ने कहा कि टीएमसी के आरोप बेबुनियाद हैं और जनता इसे मजाक के रूप में देख रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या टीएमसी हार के डर से ऐसे आरोप लगा रही है।

आधार कार्ड के स्वरूप...

के बीच अनावश्यक भ्रम पैदा कर रही हैं। मंत्रालय ने आम लोगों से अपील की है कि वे इस प्रकार की अपुष्ट खबरों और सोशल मीडिया पोस्टों पर ध्यान न दें तथा केवल भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और पीआईबी के आधिकारिक माध्यमों से जारी सूचनाओं पर ही भरोसा करें। मंत्रालय ने मीडिया संस्थानों से भी आग्रह किया है कि वे ऐसी भ्रामक सूचनाओं को प्रसारित न करें और केवल प्रमाणिक जानकारी ही साझा करें।

समाज का विश्वास ...

उद्देश्य समाज की आवाज को सत्ता तक पहुंचाना और जनभावनाओं को अभिव्यक्ति देना था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पत्र-पत्रिकाओं ने जनजागरण का सबसे प्रभावी माध्यम बनकर देश को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तिवारी ने उदाहरण देते हुए कहा कि *वंदे मातरम्* जैसे गीत केवल रचनाएं नहीं थे, बल्कि उन्होंने लोगों के भीतर राष्ट्रभाव जागृत कर आजादी की लड़ाई को नई ऊर्जा दी। तिवारी ने स्पष्ट किया कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ संविधान ने नहीं, बल्कि समाज ने बनाया है। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका की तरह मीडिया के लिए कोई औपचारिक ढांचा नहीं है, फिर भी समाज ने उसे इन तीनों पर नजर रखने और जनता की आवाज को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता की असली ताकत समाज का विश्वास है और यही उसकी सबसे बड़ी पूंजी भी है। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि समय के साथ पत्रकारिता मिशन से कमीशन की ओर बढ़ती दिख रही है। जब मीडिया सत्ता के समीकरणों में उलझता है या केवल विरोध के लिए नकारात्मकता खोजता है, तो उसकी विश्वसनीयता पर असर पड़ता है। आज के समय मीडिया पर अपनी खबरों को लेकर समाज के विश्वास को कायम रखने की सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि समाज के हित में सकारात्मक और रचनात्मक पत्रकारिता को बढ़ावा देना आवश्यक है, ताकि लोगों के सामने अच्छे कार्यों और सकारात्मक बदलावों की भी तस्वीर आ सके। संपादक तिवारी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के *पंच परिवर्तन* की अवधारणा को पत्रकारिता के लिए एक नई दिशा बताते हुए कहा कि सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी और नागरिक कर्तव्यों जैसे विषयों पर मीडिया की सक्रिय और सकारात्मक भूमिका समय की मांग है। उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे प्रयास, जैसे पर्यावरण संरक्षण या सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता, समाज में बड़े बदलाव ला सकते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रो. आनंद कुमार त्यागी ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में हेमंत गुप्त उपस्थित रहे। इस अवसर पर विभिन्न शिक्षाविदों, प्राध्यापकों और पत्रकार उपस्थिति रहे। समारोह के अंत में शिवशंकर पाण्डेय, डॉ. जिनेश पटेल, वंदना सिंह, आदर्श कुमार, सुशांत मुखर्जी और अशोक कुमार मिश्र को पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

विवेक विहार में चारमंजिला ...

रही थीं। दमकलकर्मियों और पुलिस ने संयुक्त राहत एवं बचाव अभियान चलाते हुए आग में फंसे करीब 10-15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मृतकों की पहचान की प्रक्रिया जारी है। आग पर नियंत्रण के लिए 12 दमकल गाड़ियों को बुलाया गया। इसमें घंटों का वक्त लगा। पुलिस और दमकल विभाग की टीमें आग लगने के कारणों की जांच कर रही हैं। सूत्रों का कहना है कि एसी में विस्फोट होने कारण आग लगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि भवन की सुरक्षा व्यवस्था, फायर सेफ्टी इंतजाम और निर्माण मानकों की भी जांच की जाएगी। दमकल विभाग के प्रवक्ता एके मलिक के अनुसार, इस हादसे में मरने वालों की संख्या नौ हो गई है। आग इमारत के छह फ्लैटों में रखे घरेलू सामान से फैली। राहत एवं बचाव अभियान के दौरान विभिन्न मंजिलों से नौ झुलसे शव बरामद किए गए। सभी शव दिल्ली पुलिस की क्राइम टीम को सौंपे गए हैं। प्राथमिक जानकारी के अनुसार आग इमारत के छह फ्लैटों में फैली। पहली मंजिल से एक शव, दूसरी मंजिल से पांच शव तथा सीढ़ियों के ऊपर बनी लॉक मुमटी से तीन शव बरामद किए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार मुमटी बंद थी। आशंका जताई जा रही है कि कुछ लोग धुएं और आग से बचने के लिए वहां पहुंचे, लेकिन बाहर नहीं निकल सके। दमकल विभाग ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट सहित अन्य संभावित कारणों पर भी पड़ताल की जा रही है। दमकल विभाग यह भी जांच करेगा कि इमारत में फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम थे या नहीं और कहीं सुरक्षा मानकों की अनदेखी तो नहीं की गई। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आग लगने के सटीक कारणों का खुलासा किया जाएगा।

बंगाल की फलता ...

पोलिंग स्टेशनों सहित सभी 285 पोलिंग स्टेशनों पर नए सिरे से मतदान कराया जाएगा। सभी पोलिंग स्टेशनों पर 21 मई 2026 को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच नए सिरे से मतदान कराया जाएगा; और वोटों की गिनती 24 मई, 2026 को होगी। बता दें कि पश्चिम बंगाल के 294 सीटों पर दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान हुए थे। 29 अप्रैल को मतदान के दौरान फलता सीट पर ईवीएम में छेड़छाड़ करने और टेप चिपकाने का मामला सामने आया था। इसे लेकर चुनाव आयोग ने जांच का आदेश दिया था। जांच की रिपोर्ट के बाद चुनाव आयोग ने फलता सीट पर मतदान स्थगित करने का फैसला किया है। राज्य में 4 मई को मतों की गितनी होगी। चुनाव आयोग के इस फैसले से साफ है कि इस दिन फलता विधानसभा सीट पर हुए मतदान की वोटिंग की गिनती नहीं होगी, बल्कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद 21 मई को फिर से फलता सीट पर मतदान कराये जाएंगे। चार मई को राज्य की 293 सीटों पर ही वोटों की गिनती होगी। शुक्रवार को आयोग ने घोषणा की थी कि दक्षिण 24 परगना के दो विधानसभा क्षेत्रों, डायमंड हार्बर और मगराहाट पश्चिम में कुल 15 बूथों पर फिर से चुनाव होंगे। शनिवार को भी दोनों विधानसभा क्षेत्रों में इसी तरह से फिर से चुनाव थे, लेकिन फलता सीट को लेकर शाम तक अनिश्चितता बनी हुई थी। शाम को चुनाव आयोग ने फलता को लेकर बड़ा फैसला किया। दूसरे चरण के मतदान से पहले ही दक्षिण 24 परगना जिले लगातार चर्चा में रहा था। डायमंड हार्बर पुलिस जिले के पुलिस पर्यवेक्षक अजयपाल शर्मा और फलता के तृणमूल उम्मीदवार जहांगीर खान के बीच *कोल्ड वॉर* शुरू हो गया था। मतदान के दिन फलता में ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप लगे। उसी समय, फिर से चुनाव के लिए आवेदन भी आयोग को सौंपे गए थे। किन बूथों पर फिर से चुनाव होगा, यह तय करने से पहले आयोग ने जांच की। दक्षिण 24 परगना जिले से और भी बूथों पर फिर से चुनाव के लिए आवेदन जमा किए गए थे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के निर्देश पर, कमीशन द्वारा नियुक्त स्पेशल ऑब्जर्वर सुब्रत गुप्ता, फलता, मगराहाट और डायमंड हार्बर समेत साउथ 24 परगना के अलग-अलग इलाकों में स्क्रूटनी प्रोसेस को देखने गए थे। उसके बाद उन्होंने चुनाव आयोग को रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट के आधार पर चुनाव आयोग ने यह फैसला किया। चुनाव के बाद भी फलता में तनाव बरकरार रहा। इसकी शुरुआत शुक्रवार से हुई। फलता के हाशिमनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई के आरोपों के चलते माहौल गरमा गया। शनिवार को भी इसी इलाके में तनाव फैल गया। हाशिमनगर इलाके के लोगों के एक ग्रुप, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता भी शामिल हैं, ने आरोप लगाया कि उन्हें वोट नहीं डालने दिया गया। जब उन्होंने विरोध किया, तो तृणमूल पंचायत प्रधान के नेतृत्व में कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ मारपीट की गई। शुक्रवार और शनिवार को प्रदर्शनकारियों ने दो दिनों तक नेशनल हाईवे जाम रखा। उन्होंने दोबारा चुनाव कराने की मांग की। साथ ही, तृणमूल उम्मीदवार जहांगीर खान और उनके कुछ *करीबी* नेताओं की गिरफ्तारी की मांग की गई है। ऐसे में, आयोग ने जहांगीर के करीबी लोगों के खिलाफ उन्हें धमकाने और डराने के आरोप में कार्रवाई का आदेश दिया है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें इसराफुल और जहांगीर के एक और करीबी सुजाद्दीन शेख का नाम है। आयोग के आदेश के बाद तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया।

ईरान ने अमेरिका को ...

करने की मांग की गई थी। उन्होंने कहा कि मैंने इसे अभी देखा नहीं है। मैं प्रस्ताव की समीक्षा करूंगा। इसके बाद ही हमारे रुख की मीडिया को आधिकारिक जानकारी दी जाएगी। ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत के कुछ समय बाद ट्रुथ सोशल पर लिखा कि मुझे नहीं लगता कि ईरान का शांति प्रस्ताव स्वीकार्य होगा। ईरान ने पिछले 47 वर्षों में मानवता और दुनिया के साथ जो कुछ भी किया है, उसके लिए उसने अभी पूरी कीमत नहीं चुकाई है। वह इस प्रस्ताव को एयरफोर्स वन में पढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि ईरान में सब कुछ तबाह हो चुका है। वह समझौता करने के लिए लालायित है। उन्होंने दुहराया कि अगर अमेरिका ईरान से हट भी जाए तो तबाह हुए मुल्क को खड़ा होने में 20 साल लग जाएंगे। ट्रंप ने कहा कि मुश्किल यह है कि यही समझ में नहीं आ रहा का इस समय ईरान का सर्वमान्य नेता कौन है। कभी कोई आगे आ जाता है तो कभी कोई। ऐसी स्थिति में इस बात की पक्की संभावना है कि अमेरिका फिर से कुछ ठिकानों पर सैन्य हमले शुरू कर सकता है। अगर ईरान ने कोई बेजा हरकत की तो उसके लिए बहुत बुरा होगा। ट्रंप की हमले की टिप्पणी के बाद ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने कहा कि वह अमेरिका के साथ फिर से युद्ध के लिए तैयार है। इस बीच व्हाइट हाउस ने शनिवार को पुष्टि की कि निक स्टीवर्ट ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए काम कर रही राजनयिक टीम में शामिल हो गए हैं। वह राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान विदेश विभाग के सदस्य रहे हैं। वह तेजतर्रार और अनुभवी नीति विशेषज्ञ हैं। वह विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की प्रतिभाशाली टीम के अहम सदस्य हैं। इससे पहले शनिवार दिन में ईरान के सरकारी मीडिया आउटलेट तसनीम न्यूज ने खुलासा किया था कि तेहरान ने अमेरिका को 14 सूत्रीय प्रस्ताव सौंपा है। इस सैन्य घमासान से चिंतित कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल-थानी ने शनिवार को ईरान के विदेशमंत्री अब्बास अराघची से बातचीत की है। यह तब है कि जब इजराइल और अमेरिका के हमलों के बाद दोनों देशों पर दबाव बढ़ाने के लिए कतर के नेचुरल गैस प्लांट और हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। कतर के विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार कि प्रधानमंत्री ने शांतिपूर्ण तरीकों से संकट को हल करने के उद्देश्य से किए जा रहे मध्यस्थता प्रयासों के लिए कतर राज्य के पूर्ण समर्थन की पुष्टि की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सभी पक्षों को इन प्रयासों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देनी चाहिए, जिससे बातचीत में प्रगति के लिए अनुकूल माहौल बनाने में मदद मिले और तनाव के फिर से बढ़ने का खतरा कम हो। प्रधानमंत्री अल-थानी ने कहा कि ईरान को सूझबूझ से काम लेने के साथ अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करना चाहिए।

विदेशी आक्रमणों के ...

एक व्यक्ति समाज की भलाई के लिए काम करता है और खर्च करता है, अहसान के तौर पर नहीं, बल्कि कर्तव्य समझकर। उन्होंने कहा कि दूसरों की सेवा करने से हमारा अपना विकास होता है। दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करके हम स्वयं को बेहतर करते हैं और एक बेहतर इंसान बनते हैं। यही सिद्धांत इस भारतीय भूमि का मूल मूल्य है, जिसे आमतौर पर हिंदू समाज के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि यह समाज का वह स्थायी लोकाचार है, जो हजारों से कायम है। कई कारणों से, कुछ हमारी उदासीनता के कारण और कुछ विदेशी आक्रमणों के कारण, इस लोकाचार को संरक्षित रखने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ी। आरएसएस प्रमुख ने आगे कहा कि विदेशी आक्रमणकारियों ने पाया कि समाज की यह विचारधारा, यह मूल्य प्रणाली ही इसकी आत्मा है और इसे जीवित रखने की कुंजी है। इसलिए उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि जो लोग इस आत्मा को संरक्षित करने का प्रयास करेंगे, उन्हें जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा और उन्हें घोर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि विदेशी आक्रमणों और कठिनाइयों के बावजूद, आदिवासी समुदायों और अनुसूचित जातियों ने देश की पहचान और आत्मा को संरक्षित रखा है। उन्होंने कहा कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, आदिवासी समुदायों और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समूहों से संबंधित लोगों में देश की मूल पहचान बरकरार रही। भागवत ने उन्हें मुख्यधारा की विकास प्रक्रिया में एकीकृत करने की आवश्यकता पर जोर दिया, साथ ही यह सुनिश्चित करने की बात कही कि उन्हें सेवाओं और सुविधाओं तक समान पहुंच प्राप्त हो। वैश्विक घटनाक्रमों का जिक्र करते हुए भागवत ने कहा कि वर्तमान समय में विश्व लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहा है और संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत एक स्थिर शक्ति के रूप में उभर सकता है। उन्होंने कहा कि देश को न केवल अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए बल्कि विश्व को भी समर्थन देना चाहिए। उन्होंने विश्व को यह देखना चाहिए कि देश न केवल अपने दुखों और पीड़ाओं का समाधान कर रहा है बल्कि विश्व को भी इसी तरह के मुद्दों से निपटने में मदद कर रहा है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि समाज की सेवा कोई एहसान नहीं बल्कि एक कर्तव्य है जो व्यक्ति के स्वयं के विकास में योगदान देता है। उन्होंने कहा कि दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करना भी व्यक्ति को ऊपर उठाता है और समाज के सामूहिक ताने-बाने को मजबूत करता है। भगवत ने कहा कि तथाकथित शिक्षित और विकसित वर्ग समय के साथ इन समुदायों से दूर होते चले गए हैं। उन्होंने इस खाई को पाटने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि समाज की वास्तविक पहचान इन परंपराओं और मूल्यों में निहित है, जिन्हें आदिवासी और दलित समुदायों ने संरक्षित रखा है।

इंफाल एयरपोर्ट कार्गो ...

को मणिपुर में सांप्रदायिक झड़पों की बरसी मनाई जा रही है। इसी बीच, इंफाल में बीर टिकेंद्रजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल के पास सुबह करीब 11.50 बजे एक आईईडी विस्फोट हुआ। हालांकि, सूत्रों ने बताया कि अभी तक किसी के हताहत होने या नुकसान की खबर नहीं है। विस्फोट के बाद, सुरक्षा बल और पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके को घेर लिया। विस्फोट में शामिल बदमाशों और उससे जुड़े मामलों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए तलाशी और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि, पता चला है कि विस्फोट का सही कारण और किसी भी व्यक्ति या संगठन ने अभी तक इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। फिलहाल, अधिकारी घटना की जांच कर रहे हैं। घटना के संबंध में विस्तृत सूचना का इंतजार है।

त्रिपुरा में 70 वर्षीय ...

इसे आत्महत्या यानी फांसी का मामला माना गया और उसी दिन अस्वाभाविक मौत का केस दर्ज किया गया। जांच के दौरान आज एक लिखित एफआईआर प्राप्त हुई, जिसमें आरोप लगाया गया कि मृतका के दादा ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। इस गंभीर आरोप के बाद पुलिस ने मामले को दुष्कर्म और हत्या की धाराओं में बदल दिया है और साथ ही पॉस्को एक्ट भी लागू किया गया है। सोनामुरा थाना प्रभारी तपस दास ने बताया कि सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद लगभग 70 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलने के बाद कार्रवाई की गई है और उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। फॉरेंसिक और अन्य तकनीकी साक्ष्यों को भी इकट्ठा किया जा रहा है, ताकि सच्चाई सामने आ सके।

तीसरी बार असम में सरकार बनाएगा भाजपा गठबंधन : दिलीप सैकिया

गुवाहाटी (हिंस)। असम प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने विधानसभा चुनाव की मतगणना से एक दिन पूर्व आज बड़ा दावा करते हुए कहा है कि राज्य में भाजपा गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि 126 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा गठबंधन 100 से अधिक सीटें हासिल करेगा। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि अकेले भाजपा 80 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेगी, जो पार्टी के प्रति जनता के भरोसे को दर्शाता है। विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए सैकिया ने कहा कि मतगणना के दिन सुबह करीब 10-30 बजे तक विपक्षी दल सरकार बनाने का दावा करते रहेंगे, लेकिन उसके बाद रुझान पूरी तरह स्पष्ट हो जाएंगे और भाजपा गठबंधन 100 से अधिक सीटों के साथ सरकार बनाता नजर आएगा। मतगणना से ठीक पहले दिए गए इस बयान को राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि सभी दल चुनाव परिणामों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

मिजोरम : फर्जी अदालती आदेशों का इस्तेमाल करके 16 दोषियों की रिहाई की जांच के लिए एसआईटी गठित

एजल। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि दक्षिण मिजोरम के लुंगलेई जिला जेल में हुए एक बड़े घोटाले की जांच के लिए चार सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है , जहां फर्जी अदालती दस्तावेजों का उपयोग करके कई महीनों में 16 दोषियों को गैरकानूनी रूप से रिहा कर दिया गया था। लुंगलेई के पुलिस अधीक्षक जे. लालमुआनकिमा ने कहा कि यह घटना हाल ही में पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज होने के बाद ही सामने आई। उनके अनुसार, दोषियों ने जाली मुहरों वाले फर्जी अदालती आदेश प्रस्तुत करके अपनी रिहाई सुनिश्चित कर ली, जिससे जेल अधिकारियों को यह विश्वास हो गया कि वे असली थे। उन्होंने बताया कि अनियमितता का पता चलते ही पुलिस ने तुरंत तलाशी अभियान शुरू कर दिया। अब तक रिहा किए गए 12 दोषियों को दोबारा गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक की रिहाई के बाद मौत हो गई। शेष तीन का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। प्रारंभिक जांच में 22 वर्षीय कैदी जेरेमी लालथांगतुरा को इस पूरे मामले का मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है। ऑनलाइन धोखाधड़ी सहित कई आरोपों का सामना कर रहे जेरेमी को शुक्रवार को आगे की पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया। इस जांच का नेतृत्व कर रही एसआईटी (विशेष सूचना सेवा समिति) का नेतृत्व लुंगलेई उपमंडल पुलिस अधिकारी आर. थैंकिमा कर रहे हैं। लालमुआनकिमा ने कहा कि जांच आगे बढ़ रही है और जल्द ही और अधिक जानकारी मिलने की उम्मीद है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अभी यह पुष्टि करना जल्दबाजी होगी कि इसमें किसी तरह के अंदरूनी या बाहरी सहयोगियों की संलिप्तता थी या नहीं। जेल अधिकारियों ने कहा कि धोखाधड़ी की यह गतिविधि इस साल की शुरुआत में शुरू हुई थी, लेकिन पिछले सप्ताह तक इसका पता नहीं चल पाया था। यह मुद्दा तब सामने आया जब लुंगलेई जिला और सत्र न्यायालय के अधिकारी कुछ कैदियों की रिहाई के आदेशों का समर्थन करने वाले रिकॉर्ड खोजने में विफल रहे, जिससे संदेह पैदा हुआ। इसके बाद 25 अप्रैल को एक औपचारिक शिकायत दर्ज की गई, जिससे जांच शुरू हुई। लुंगलेई जिला जेल के उप अधीक्षक लालरुअत्सांगा ने कहा कि फर्जी रिहाई आदेश जाली मुहरों और प्रारूपण सहित असली अदालती दस्तावेजों से काफी मिलते-जुलते थे। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि जेल अधिकारियों को अदालत के आदेशों का बिना देरी किए पालन करना होता है, इसलिए दस्तावेजों को शुरू में प्रामाणिक मान लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप कैदियों को रिहा कर दिया गया।

जापानी यात्रा समाप्त कर मुख्यमंत्री डॉ. शर्मा पहुंचे गुवाहाटी

गुवाहाटी (हिंस)। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा जापान की यात्रा समाप्त कर आज गुवाहाटी पहुंच गए। सोमवार को असम विधानसभा चुनाव परिणामों के दिन से एक दिन पहले मुख्यमंत्री जापान से गुवाहाटी लौट आए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. शर्मा बीती रात दिल्ली में बिताने के बाद आज सुबह गुवाहाटी लौटे आए। दिल्ली से मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्घेरिटा, असम सरकार के मंत्री जयंतमल्ल बरुवा और कार्बी आंगलोंग स्वायत्तशासी परिषद के सीईएम तुलिराम रंग्हांग गुवाहाटी पहुंचे हैं। ज्ञात हो कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान को पूरा करे करने के बाद मुख्यमंत्री जापान गए थे। पश्चिम बंगाल में भाजपा स्टार प्रचारक के रूप में प्रचार अभियान में मुख्यमंत्री ने भाजपा के लिए जमकर प्रचार किया था। पार्टी सूत्रों के अनुसार गुवाहाटी में उपस्थित होते ही मुख्यमंत्री आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पार्टी उम्मीदवारों के साथ एक समीक्षा बैठक में भी शामिल होने वाले है।

कोरिडांग उपचुनाव मतगणना नागालैंड में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

कोहिमा। नागालैंड में अधिकारियों ने कोरिडांग विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती की तैयारियां पूरी कर ली हैं, जो 4 मई को मोकोकचुंग जिले में होने वाली है। भाजपा के मौजूदा विधायक इम्कोंग एल इम्चेन के निधन के कारण उपचुनाव कराना आवश्यक हो गया था। 9 अप्रैल को हुए मतदान में 82.21 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जिसमें 30 मतदान केंद्रों पर कुल 22,382 मतदाताओं में से 18,400 मतदाताओं ने अपने मत डाले। इस सीट पर कुल छह उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने दाओचिर आई इम्चेन को मैदान में उतारा है, जिन्हें सत्तारूढ़ पीपुल्स डेमोक्रेटिक अलायंस का सर्वसम्मत उम्मीदवार होने का समर्थन प्राप्त है। अन्य दावेदारों में कांग्रेस के उम्मीदवार टी चालुकुम्बा आओ, एनपीपी के आई अबेनजांग, साथ ही निर्दलीय उम्मीदवार इम्चाटोबा इम्चेन, इम्तिवापांग और तोशिकाबा शामिल हैं। रिटर्निंग ऑफिसर नॉकपाई कोन्यक के अनुसार, मोकोकचुंग में डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय में मतगणना केंद्र पूरी तरह से तैयार है, जिसमें मतगणना अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और उम्मीदवारों के एजेंटों के लिए अलग-अलग स्थान निर्धारित किए गए हैं ताकि प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। एक रिपोर्ट के अनुसार, मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी और तीन चरणों में 10 मेजों पर की जाएगी। इस महीने की शुरुआत में चुनाव से संबंधित हिंसा की घटनाओं को देखते हुए, जिनमें एक व्यक्ति की मौत हुई और संपत्ति को नुकसान पहुंचा, अधिकारियों ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी है। इनमें बलों की बहुस्तरीय तैनाती, सीसीटीवी निगरानी और मतगणना स्थल तक नियंत्रित पहुंच शामिल हैं।

गुवाहाटी में स्वच्छता अभियान दो का शुभारंभ, नागरिकों से सहयोग की अपील

गुवाहाटी (हिंस)। गुवाहाटी नगर निगम (जीएमसी) द्वारा लताशील खेल मैदान, गुवाहाटी में रविवार *गुवाहाटी स्वच्छता अभियान 2* का शुभारंभ समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए विभिन्न कदम उठाने की घोषणा की गई। इस अवसर पर अधिकारियों ने बताया कि पिछले वर्ष स्वच्छता अभियान (स्वच्छ सर्वेक्षण) के तहत गुवाहाटी ने 44वां स्थान प्राप्त किया था। इस वर्ष इससे बेहतर रैंक हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए प्रशासन के साथ-साथ आम जनता की सक्रिय भागीदारी को बेहद आवश्यक बताया गया। कार्यक्रम में गुवाहाटी नगर निगम के महापौर मृगेन शरनिया, जीएमसी के आयुक्त चिन्मय प्रकाश फुकन, अतिरिक्त आयुक्त ध्रुवज्योति हजारिका, सहित निगम के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

मणिपुर में विभाजन अभी भी कायम है : जातीय हिंसा के तीन साल पूरे होने पर रैलियां और बंद जारी किए गए

इंफाल। मणिपुर में हुई जातीय हिंसा की तीसरी बरसी रविवार को राज्य के विभिन्न हिस्सों में रैलियों, सार्वजनिक सभाओं और बंद के साथ मनाई गई, जो मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जारी विभाजन को दर्शाती है। पहाड़ी जिलों में मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग के विरोध में आयोजित *आदिवासी एकजुटता मार्च* के बाद 3 मई, 2023 को शुरू हुए इस संघर्ष में अब तक कम से कम 260 लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं। इस अशांति के कारण राज्य में एक वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन भी लागू करना पड़ा। दोनों समुदायों द्वारा अलग-अलग स्मृति समारोह आयोजित किए गए। इंफाल घाटी में, मैतेई समूहों ने कई जिलों में जुलूस निकाले, जिसमें अगली जनगणना से पहले राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को लागू करने और राज्य की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने की मांग उठाई गई। संयुक्त सुरक्षा समिति के बैनर तले बिष्णुपुर जिले के नामबोल में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। इसी बीच, इंफाल पूर्व में, इबोयाइमा शुमांग लीला शांगलेन में चल रहे संकट पर एक सार्वजनिक चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें मीरा पैबी और मणिपुर अखंडता समन्वय समिति (सीओकोमी) के सदस्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने हिंसा से प्रभावित लोगों के लिए न्याय और जवाबदेही की मांग की। घाटी के कई जिलों में 100 से अधिक मैतेई पीड़ितों की याद में पुष्पांजलि भी अर्पित की गई। इसके विपरीत, कुकी-जो संगठनों ने इस दिन को बंद और स्मारक सभाओं के साथ मनाया। जनजातीय एकता समिति (सीओटीयू) के आह्वान के बाद कांगपोकपी जिले में 12 घंटे का बंद रहा, जिसके परिणामस्वरूप व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। यह समूह मैतेई समुदाय के साथ गहरे मतभेदों का हवाला देते हुए कुकी समुदाय के लिए एक अलग प्रशासनिक व्यवस्था की मांग कर रहा है। चुराचंदपुर में, स्वदेशी जनजातीय नेताओं के मंच (आईटीएलएफ) और जोमी परिषद (जेडसी) द्वारा अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां हिंसा में मारे गए लोगों के लिए प्रार्थनाएं की गईं और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। फाईजांग के शहीद कब्रिस्तान में, लोग 100 से अधिक कुकी-जो पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए। कुछ कुकी-जो समूहों द्वारा इस दिन को *पृथक्करण दिवस* के रूप में भी मनाया गया। सामुदायिक नेताओं ने संघर्ष के दौरान हुए भयावह प्रभावों पर प्रकाश डालते हुए सैकड़ों लोगों की मौत, व्यापक विस्थापन, हजारों घरों के विनाश और पूजा स्थलों को हुए नुकसान का दावा किया। मणिपुर की जनसांख्यिकीय संरचना तनाव का मुख्य कारण रही है, जिसमें इंफाल घाटी में मैतेई समुदाय के लोग बहुमत में हैं, जबकि कुकी और नागा सहित आदिवासी समूह मुख्य रूप से पहाड़ी जिलों में निवास करते हैं। लंबे समय तक चले इस अशांति के कारण राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुई, जिसका परिणाम पिछले साल फरवरी में एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के इस्तीफे के रूप में सामने आया। इसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया और राज्य विधानसभा को निलंबित अवस्था में रखा गया। इस व्यवस्था को बाद में इसी साल फरवरी में हटा लिया गया, जिससे वाई खेमचंद सिंह के नेतृत्व वाली नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ।

ढकुवाखना में भयावह आग व्यावसायिक प्रतिष्ठान जलकर राख

लखीमपुर (हिंस)। असम के लखीमपुर जिलांतर्गत ढकुवाखना में गांधी मैदान के समीप एक भयावह आग की घटना सामने आई है, जिसमें एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूरी तरह जलकर राख हो गया। रविवार को प्राप्त जानकारी के अनुसार, स्थानीय लोगों ने अचानक गांधी मैदान के पास स्थित एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान में आग लगते हुए देखा। देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरे प्रतिष्ठान को अपनी चपेट में ले लिया और स्थिति भयावह हो गई। घटना की सूचना मिलते ही ढकुवाखना अग्निशमन विभाग की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बावजूद आग पर पूरी तरह से काबू पाने में कठिनाई सामने आई। देर रात तक अग्निशमन कर्मी स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाने का प्रयास करते रहे। इस आग में प्रतिष्ठान की लाखों रुपए की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई।

चार मई को मतगणना के लिए कोकराझाड़ पूरी तरह तैयार

कोकराझाड़(हिंस)। असम विधानसभा आम चुनाव 2026 के तहत चार मई को होने वाली मतगणना को लेकर कोकराझाड़ जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस संबंध में जिला आयुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. पी उदय प्रवीन ने आज जिला आयुक्त कार्यालय स्थित सम्मेलन कक्ष में आयोजित एक संवाद समेलन में मीडिया को विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मतगणना सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगी। सबसे पहले डाक मतपत्रों (पोस्टल बैलेट) की गणना की जाएगी, इसके बाद ईवीएम में दर्ज मतों की गिनती शुरू होगी। मतगणना प्रक्रिया को सुचारु, पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतगणना कार्य के लिए लगभग 500 कर्मियों की तैनाती की गई है, जिनमें काउंटिंग सुपरवाइजर, काउंटिंग असिस्टेंट, माइक्रो ऑब्जर्वर तथा अन्य कर्मचारी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त पांच मतगणना प्रेक्षक भी कोकराझाड़ पहुंच चुके हैं और सर्किट हाउस में ठहरे हुए हैं। इनमें कृष्ण कुमार सिंह को 01-गोसाईगांव, रामजी मिश्रा को 02- दोतमा (एसटी), परदेशी सिद्धार्थ कोमल को 03-कोकराझाड़ (एसटी), दया किशन शर्मा को 04-बाओखुंगरी तथा सौरव कुमार सिन्हा को 05- पर्वतझोड़ा विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मतगणना राउंड की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 01-गोसाईगांव विधानसभा क्षेत्र में 5 प्रत्याशियों के लिए 11 राउंड, 02- दोतमा (एसटी) में 5 प्रत्याशियों के लिए 13 राउंड, 03-कोकराझाड़ (एसटी) में 6 प्रत्याशियों के लिए 14 राउंड, 04-बाओखुंगरी में 12 प्रत्याशियों के लिए 16 राउंड तथा 05- पर्वतझोड़ा में 8 प्रत्याशियों के लिए 17 राउंड में मतगणना पूरी की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था के बारे में उन्होंने बताया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। इसके तहत मतगणना केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में भीड़ जुटाने पर रोक रहेगी। केवल वैध पहचान पत्रधारकों को ही प्रवेश दिया जाएगा तथा मोबाइल फोन एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रवेश पर भी निर्धारित क्षेत्रों में प्रतिबंध रहेगा। जिला आयुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रशासन स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतगणना कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा सभी नागरिकों और संबंधित पक्षों से सहयोग की अपील की है।

कामरूप (मेट्रो) जिले में आज ड्राई डे घोषित

गुवाहाटी (हिंस)। कामरूप (मेट्रो) जिला प्रशासन ने मतगणना प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए 4 मई को जिले में ड्राई डे घोषित किया है। इस संबंध में जिला आयुक्त द्वारा आदेश जारी किया गया है, ताकि मतगणना की प्रक्रिया सुचारु और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। जारी निर्देश के अनुसार, सभी थोक और खुदरा शराब की दुकानें, गोदाम तथा इंडियन मेड फॉरेन लिकर (आईएमएफएल) और देशी शराब बेचने वाले प्रतिष्ठान मतगणना प्रक्रिया पूरी होने तक बंद रहेंगे। इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की शराब के परिवहन पर भी सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, क्लब, बार, होटल, लघु स्तर के शराब निर्माण इकाइयों और स्थानीय डिस्टिलरी को भी ड्राई डे लागू रहने तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है। जिला प्रशासन ने सभी लाइसेंसधारी व्यापारियों और आम जनता से आदेश का कड़ाई से पालन करने की अपील की है।

पूसीरे की आरपीएफ ने कई रेस्क्यू अभियानों में यात्रियों और नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित की

गुवाहाटी (हिंस)। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (पूसीरे) की रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने हाल के दिनों में अपने क्षेत्राधिकार में चलाए गए सफल रेस्क्यू अभियानों की एक श्रृंखला के माध्यम से, यात्रियों की सुरक्षा और मानवीय सेवा के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता को एक बार पुनः साबित किया है। पूसीरे के सीपीआरओ कपिंजल किशोर शर्मा ने बताया कि 24 से 30 अप्रैल की अवधि के दौरान, आरपीएफ कर्मियों ने विभिन्न रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों से बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को रेस्क्यू किया, जो असुरक्षित थे। उनमें घर से भागे हुए नाबालिग और व्यथित यात्री भी शामिल थे। एक बड़े अभियान में, डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ कर्मियों ने एक ट्रेन से 12 नाबालिग लड़कों को रेस्क्यू किया और उचित देखभाल तथा सुरक्षा के लिए सभी को चाइल्डलाइन अधिकारियों को सुरक्षित रूप से सौंप दिया। इसी तरह गुवाहाटी, लामडिंग, किशनगंज, कोकराझाड़, हासिमारा, मरियानी और न्यू अलीपुरद्वार जैसे स्टेशनों पर भी कई रेस्क्यू अभियान चलाए गए, जहां घर से भागे हुए कई नाबालिग लड़कों और लड़कियों का पता लगाया कर सभी को रेस्क्यू किया गया। विशेष रूप से, मरियानी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने तीन नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू किया, जबकि गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर, समय पर हस्तक्षेप के बाद नाबालिगों को उनके परिवारों से सुरक्षित रूप से मिला दिया। अलग-अलग घटनाओं में किशनगंज, लामडिंग, डिमापुर और कोकराझाड़ जैसे स्टेशनों पर रेस्क्यू किए गए नाबालिगों को सुरक्षित अभिरक्षा और पुनर्वास के लिए चाइल्ड हेल्प लाइन तथा अन्य अधिकृत एजेंसियों को सौंप दिया गया। नाबालिगों को रेस्क्यू करने के अलावा, आरपीएफ कर्मियों ने व्यथित यात्रियों को भी तत्काल सहायता प्रदान की। न्यू जलपाईगुड़ी में, सांस संबंधी बीमारी से ग्रस्त एक यात्री को तत्काल चिकित्सा उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। रायगंज और बारसोई में हुई अन्य घटनाओं में, गिरने से घायल हुए यात्रियों को समय पर चिकित्सा सहायता प्रदान की गई, जो आरपीएफ कर्मियों की सतर्कता और तत्परता को दर्शाता है। पूसीरे नेटवर्क पर आरपीएफ कर्मियों के निरंतर प्रयास यात्रियों की सुरक्षा करने, मानव तस्करी को रोकने और असुरक्षित व्यक्तियों के कल्याण को सुनिश्चित करने के प्रति उनके समर्पण को दर्शाते हैं।

रंगिया रेल स्टेशन पर 60 ग्राम ड्रग्स के साथ तस्कर गिरफ्तार

रंगिया (विभास)। रंगिया रेलवे पुलिस ने डाउन शिलचर-रंगिया एक्सप्रेस ट्रेन से बिहार जा रहे एक व्यक्ति को बड़ी मात्रा में हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। बिहार के बरौनी निवासी रामू राय ड्रग्स की तस्करी कर रहा था। रेलवे पुलिस के प्रभारी अधिकारी गुणजित पाठक के नेतृत्व में चलाए गए नियमित तलाशी अभियान के दौरान रामू पर संदेह हुआ। तलाशी लेने पर उसके पास 5 साबुन के बक्सों में छिपाकर रखी 60 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। जानकारी के अनुसार, रामू राय पूर्व में भी ड्रग्स तस्करी के मामले में जेल जा चुका है। समाचार लिखे जाने तक रंगिया रेलवे पुलिस थाने में उसकी पूछताछ जारी है। पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, विशेष पर्यवेक्षक और जिला आयुक्त ने अमिनगांव में मतगणना व्यवस्था की समीक्षा की

रंगिया (विभास)। असम विधानसभा के साधारण चुनाव, 2026 की मतगणना के संदर्भ में आज अमिनगांव में स्थापित मतगणना केंद्रों की व्यवस्था और तैयारी के बारे में असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग गोयल ने विस्तृत समीक्षा की। इस समीक्षा बैठक में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त विशेष पर्यवेक्षक मंजीत सिंह और कामरूप जिले के जिला आयुक्त तथा जिला निर्वाचन अधिकारी देव कुमार मिश्र उपस्थित रहे। समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने मतगणना के संदर्भ में समग्र तैयारी, लॉजिस्टिक व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और मतगणना प्रक्रिया के लिए निर्धारित नीति-निर्देशनों के पालन की दिशाओं का विस्तार से पर्यालोचना की। उन्होंने स्ट्रांग रूम, मतगणना कक्ष, प्रवेश और प्रस्थान पथ, गणना कर्मियों के लिए की गई व्यवस्था आदि का निरीक्षण कर वोट गणना प्रक्रिया सुचारू रूप से, पारदर्शी और कार्यकुशलता से संपन्न हो सके, इसके लिए अपनाई गई व्यवस्थाओं को समझा। इसके अलावा अधिकारियों ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ पर्याप्त अधिकारी-कर्मचारी नियोजन, वाहनों की गति-पथ, संचार व्यवस्था और मतगणना के दिन संभावित किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए अपनाई गई वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर विस्तृत चर्चा की। इस मौके पर मतगणना प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर पारदर्शिता बनाए रखने और भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का कठोरता से पालन करने पर विशेष जोर दिया गया। बताया गया है कि इस समीक्षा बैठक का मुख्य उद्देश्य मतगणना से पूर्व क्षेत्र स्तर की तैयारी का मूल्यांकन करना और किसी भी संभावित त्रुटि को पूर्वानुमान से चिन्हित कर आवश्यक व्यवस्था अपनाना था। अधिकारियों ने समग्र तैयारी पर संतोष व्यक्त करते हुए संबंधित सभी को सजग रहकर दायित्वों का पूर्णतः पालन करने का निर्देश दिया। इस समीक्षा बैठक में कामरूप जिले के जिला विकास आयुक्त सुशांत कुमार दत्त, अतिरिक्त जिला आयुक्तगण, रिटर्निंग अधिकारीगण, निर्वाचन अधिकारी डॉ. भूपाली कश्यप और जिला प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। उल्लेख्य है कि वोट गणना के लिए विधानसभा क्षेत्र के आधार पर वोटग्रहण केंद्र, गणना टेबल और गणना चक्र की संख्या- 27 नं. चमरिया विधानसभा क्षेत्र में कुल वोटग्रहण केंद्र 297, गणना टेबल 14 और वोट गणना राउंड 22 है। 28 नं. बोको-छयगांव (अनुसूचित जनजाति) विधानसभा क्षेत्र में कुल वोटग्रहण केंद्र 241, गणना टेबल 14, वोट गणना राउंड 18 है। 29 नं. पलाशबाड़ी विधानसभा क्षेत्र में कुल वोटग्रहण केंद्र 278, गणना टेबल 14, वोट गणना राउंड 20, 30 नं. हाजो-शुवालकुची (अनुसूचित जाति) विधानसभा क्षेत्र में कुल वोटग्रहण केंद्र 243, गणना टेबल 14, वोट गणना राउंड 18 है । वहीं 31 नं. रंगिया विधानसभा क्षेत्र में कुल वोटग्रहण केंद्र 265, गणना टेबल 14, मतगणना राउंड 19 और 32 नं. कमलपुर विधानसभा समष्ठि में कुल वोटग्रहण केंद्र 231, गणना टेबल 14, मतगणना 17 राउंड में समाप्त होगी।

धुबड़ी : पांच विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना की तैयारियां पुरी

धुबड़ी (विभास)। देश के पांच राज्य सहित धुबड़ी जिले के पांच विधानसभा क्षेत्रों में 4 मई को मतगणना निर्धारित की गई है। इस दौरान जिले में मतगणना केंद्र के आसपास भीड़ इकट्ठा, नारेबाजी तथा विजय जुलूस निकालना प्रतिबंध है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जिला मजिस्ट्रैट द्वारा भारतीय संहिता धारा 2023 के तहत धारा 163 लगाई गई है। इसके अलावा मतगणना केंद्र के मुख्य द्वार के निर्धारित दायरे के आसपास आमलोग व वाहनों की पार्किंग करना मना है। चुनाव अधिकारी के निर्देश अनुसार बिना पहचान पत्र के मतगणना केंद्र में प्रवेश निषेध है। साथ ही मतगणना केंद्र के आसपास दिहाड़ी व दुकान लगाना पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अगर कोई चुनाव अधिकारी के इस आदेश को पालन नहीं करता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

संपादकीय

धैर्य रखें

धैर्य रखें एआईएमआईएम के वरिष्ठ सांसद असदुद्दीन ओवैसी के तेवर पाकिस्तान के खिलाफ तो तलख हैं ही साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार को भी बृहस्पतिवार को चुनौती देते हुए कहा कि इस बार सिर्प घर में घुस कर मारने की ही बात न हो बल्कि घुसकर बैठकर बैठ जाने की बात भी होनी चाहिए। ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को याद दिलाया कि संसद पहले ही पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) को भारत का हिस्सा मान चुकी है ऐसे में अब वक्त है कि सरकार जमीन पर भी उसी संकल्प को लाए। ओवैसी ने केंद्र सरकार को सलाह देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान की तरफ से नियंत्रण रेखा के पास कुछ इलाके खाली कर दिए गए हैं तो भारत को इस बार वहां सिर्फ हमला ही नहीं, बल्कि वहां कब्जा भी कर लेना चाहिए। इसका मतलब है कि सांसद असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान के खिलाफ इस बार ऐसी कार्रवाई चाहते हैं कि मारो भागो जैसा न रहे बल्कि सबक सिखाने के लिए पर्याप्त रहे। बुधवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी पहलगाम में मारे गए शुभम द्विवेदी के कानपुर स्थित निवास पर जाकर इतने भावुक हो गए कि उन्होंने प्रधानमंत्री से शीघ्रातिशीघ्र पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का आग्रह किया। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि उनकी दादी इंदिरा जी होती तो अभी तक पाकिस्तान पर हमला कर देतीं। इसी तरह जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कांफ्रेंस के नेता फारूख अब्दुल्ला कहते हैं कि वह हमेशा ही दोनों देशों के बीच बातचीत के समर्थक रहे हैं किन्तु पाकिस्तान की हैवानियत से अब यही कहूंगा कि अब प्रधानमंत्री उसे जल्दी से जल्दी ऐसा सबक सिखाएं कि वह दुबारा ऐसा दुःसाहस न कर सके। इसमें कोई भी संदेह नहीं कि इन तीनों नेताओं इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री से आग्रह कर रहे हैं कि वह पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करें तो इसका मतलब है कि उन्हें जनभावनाओं का अच्छा अनुमान है। ये नेता जनता के बीच में ही रहते हैं, यही कारण है कि ये भी वह सोचते हैं जो आम जनता की सोच रही है। बहरहाल यह सेना का काम है कि वह हमले का स्थान, समय और लक्ष्य खुद निर्धारित करे। सरकार तो मात्र अनुमति ही दे सकती है। देश की जनता भी इस तथ्य को जानती है कि पूर्ण स्तर पर युद्ध से तबाही मानवता के लिए विभीषिका साबित होती है, यही कारण है कि दोनों देशों में से कोई भी विस्तारित युद्ध के पक्ष में नहीं होगा। किन्तु भारत अब जितना कदम बढ़ा चुका है वह युद्ध की शुरुआत ही तो है। यही कारण देश में इस बात की आम सहमति है कि सेना पाकिस्तान की धरती पर ही हमला करेगी इसका विस्तार और परिणाम जो भी होगा, सेना तात्कालिक निर्णय की रणनीति अपनाएगी। इतना तो निति है कि भारत सरकार सेना को संसाधन मुहैया कराने का सार्थक प्रायास कर रही है और दुनिया भर में अपने देश के पक्ष में माहौल बनाने में सफलता हासिल करने के लिए भी हरसंभव प्रायास कर रही है। सरकार ने अभी तक तो स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी राष्ट्रीय एकता और अखण्डता के लिए किसी भी हालात में अपने मित्र या शत्रु देश के दबाव में आने वाली नहीं है। भारत कार्रवाई में उतना ही विस्तार सुनिति करेगा जिसमें वह सफलता हासिल कर ले। भारत को अच्छी तरह पता है कि जब एक बार युद्ध छिड़ जाता है तो किसी दूसरे देश के सामने गिड़गिड़ाने से मदद भीख में नहीं मिलती। मदद उसे ही मिलती है जो सक्षम होता है।यही कारण है कि भारत की सेना जब भी पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेगी तो न ही किसी देश की मदद से और न ही किसी देश के निर्देशन में। वह कार्रवाई के सारे आयामों का अध्ययन और निर्धारण खुद ही करेगी। सच तो यह है कि सरकार बार-बार दोहरा रही है कि इस बार उरी और बालाकोट की तरह सीमित लक्षित हमले नहीं होंगे बल्कि आतंकवाद के आकाओं को ही निशाना बनाया जाएगा। मतलब कि सीधे आसिफ मुनीर और हाफिज सईद तथा पीओके है हमारे राजनेता इतना तो समझते ही हैं कि जब लक्ष्य बड़ा होता है तो रणनीति के अनुरूप प्राहार में समय भी लगता है। इसलिए राजनेताओं से उम्मीद की जानी चाहिए कि वे पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई हेतु न खुद धैर्य रखें बल्कि, जो लोग उन्हें अपना आदर्श मानते हैं उन्हें भी वास्तविकता से अवगत कराए कि यह वक्त धैर्य रखने का है अपनी सेना को तैयारी करने दें और पाकिस्तान को भयभीत होने दें।

ओवैसी ने केंद्र सरकार को सलाह देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान की तरफ से नियंत्रण रेखा के पास कुछ इलाके खाली कर दिए गए हैं तो भारत को इस बार वहां सिर्फ हमला ही नहीं, बल्कि वहां कब्जा भी कर लेना चाहिए। इसका मतलब है कि सांसद असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान के खिलाफ इस बार ऐसी कार्रवाई चाहते हैं कि मारो भागो जैसा न रहे बल्कि सबक सिखाने के लिए पर्याप्त रहे। बुधवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी पहलगाम में मारे गए शुभम द्विवेदी के कानपुर स्थित निवास पर जाकर इतने भावुक हो गए कि उन्होंने प्रधानमंत्री से शीघ्रातिशीघ्र पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का आग्रह किया। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि उनकी दादी इंदिरा जी होती तो अभी तक पाकिस्तान पर हमला कर देती। इसी तरह जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कांफ्रेंस के नेता फारूख अब्दुल्ला कहते है कि वह हमेशा ही दोनों देशों के बीच बातचीत के समर्थक रहे हैं किन्तु पाकिस्तान की हैवानियत से अब यही कहूंगा कि अब प्रधानमंत्री उसे जल्दी से जल्दी ऐसा सबक सिखाएं कि वह दुबारा ऐसा दु:साहस न कर सके।

परिणामस्वरूप उत्पादन में गिरावट आती है, जो कई मामलों में 10 से 50 प्रतिशत तक पहुंच सकती है

हीटवेव की मार से हरियाणा–पंजाब की खेती और किसानों की आय दोनों संकट में

जलवायु परिवर्तन के इस निर्णायक दौर में चरम गर्मी अब केवल एक मौसमी विचलन नहीं रह गई है, यह एक गहरे संरचनात्मक संकट के रूप में उभर रही है, जो वैश्विक खाद्य प्रणालियों की बुनियाद को हिला रही है। बढ़ते तापमान और तीव्र होती हीटवेव्स ने कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य आपूर्ति शृंखलाओं को एक ऐसे दबाव में ला खड़ा किया है, जहां हर कड़ी कमजोर पड़ती दिख रही है। वैज्ञानिक और नीति-निर्माता अब इसे एक "रिस्क मल्टीप्लायर" के रूप में पहचान रहे हैं—ऐसा कारक जो न केवल स्वयं नुकसान पहुंचाता है, बल्कि अन्य जोखिमों को भी कई गुना बढ़ा देता है। यदि अब निर्णायक कदम नहीं उठाए गए, तो चरम गर्मी आने वाले दशकों में वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा व्यवस्थित खतरा बन जाएगी। चरम तापमान का सबसे प्रत्यक्ष और स्पष्ट प्रभाव फसलों पर पड़ता है। यह स्थापित तथ्य है कि 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान गेहूं, चावल और मक्का जैसी प्रमुख फसलों के लिए प्रतिकूल होता है। अधिक तापमान पौधों की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को बाधित करता है, परागण को प्रभावित करता है और दानों के विकास को अधूरा छोड़ देता है। परिणामस्वरूप उत्पादन में गिरावट आती है, जो कई मामलों में 10 से 50 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। यह केवल मात्रा की समस्या नहीं है—गर्मी के कारण अनाज का पोषण स्तर भी घटता है, जिससे खाद्य गुणवत्ता प्रभावित होती है। इस प्रकार, यह संकट उत्पादन और पोषण दोनों को एक साथ चोट पहुंचाता है। पशुपालन क्षेत्र भी इस तापीय दबाव से अछूता नहीं है। उच्च तापमान के कारण पशुओं में हीट स्ट्रेस बढ़ता है, जिससे उनकी उत्पादकता पर सीधा असर पड़ता है। डेयरी पशुओं में दूध उत्पादन में कमी, मुर्गियों में अंडा उत्पादन का घट जाना और सूअरों में वृद्धि दर का धीमा होना इसके प्रमुख उदाहरण हैं। चरम परिस्थितियों में पशुओं की मृत्यु तक हो सकती है, जिससे किसानों की आय पर गंभीर चोट पड़ती है। मत्स्य पालन में स्थिति और भी जटिल हो जाती है—समुद्री तापीय लहरों के कारण जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा घटती है, जिससे मछलियां तनावग्रस्त हो जाती हैं और उनका जीवित रहना कठिन हो जाता है। इस तरह, अत्यधिक गर्मी खाद्य उत्पादन के सभी प्रमुख स्रोतों को एक साथ प्रभावित कर रही है। लेकिन असली चुनौती तब सामने आती है जब ये प्रभाव एक-दूसरे को बढ़ाने लगते हैं। चरम गर्मी सूखे को जन्म देती है, जिससे जल संसाधनों पर अभूतपूर्व दबाव पड़ता है। सिंचाई के लिए पानी की कमी फसलों की उत्पादकता को और घटा देती है, जबकि पशुओं और मनुष्यों के लिए जल संकट गंभीर रूप ले लेता है। इसके अलावा, उच्च तापमान कीटों और रोगों के प्रसार के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करता है। टिड्डी दल जैसी घटनाएं अधिक बार और अधिक तीव्रता से देखने को मिल रही हैं, जो कुछ ही दिनों में विशाल फसल क्षेत्र को नष्ट कर सकती हैं। इस

प्रकार, तापमान वृद्धि केवल एक अलग-थलग समस्या नहीं, बल्कि एक ऐसे चक्र का हिस्सा है जो लगातार खुद को मजबूत करता जाता है। वन क्षेत्रों में भी इसका गहरा प्रभाव दिखाई देता है। बढ़ती गर्मी और सूखे के कारण जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे जैव विविधता को नुकसान पहुंचता है और कार्बन चक्र बाधित होता है। यह एक खतरनाक दुष्चक्र को जन्म देता है—जंगलों की आग से कार्बन उत्सर्जन बढ़ता है, जो आगे तापमान वृद्धि को और तेज करता है, और यह वृद्धि फिर नई आग की घटनाओं को जन्म देती है। इस चक्र का प्रभाव अंततः कृषि और खाद्य प्रणालियों पर ही पड़ता है। चरम गर्मी का एक महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर अनदेखा पहलू श्रम उत्पादकता पर इसका प्रभाव है। कृषि क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक, विशेषकर विकासशील देशों में, अत्यधिक तापमान के कारण काम करने में असमर्थ हो जाते हैं। जब "गीला बल्ब तापमान" एक निश्चित सीमा से ऊपर पहुंच जाता है, तो मानव शरीर के लिए लंबे समय तक काम करना जानलेवा हो सकता है। यह स्थिति एक प्रकार का "हीट-इकोनॉमी ट्रैप" पैदा करती है, जहां गर्मी सीधे श्रम, उत्पादन और आय—तीनों को सीमित कर देती है। अनुमान है कि दक्षिण एशिया जैसे क्षेत्रों में साल के सैकड़ों दिन ऐसे हो सकते हैं, जब श्रमिकों के लिए काम करना संभव नहीं रहेगा। इसका सीधा असर किसानों और मजदूरों की आय पर पड़ता है, जिससे आर्थिक असुरक्षा बढ़ती है। इन सभी प्रभावों का सम्मिलित परिणाम एक "कैस्केडिंग फेल्योर" के रूप में सामने आता है। जब फसलें असफल होती हैं, पशुधन प्रभावित होता है और श्रमिक काम नहीं कर पाते, तो खाद्य आपूर्ति शृंखला टूटने लगती है। इसका सीधा असर बाजार पर पड़ता है—खाद्य कीमतें बढ़ती हैं, जिससे गरीब और कमजोर वर्गों के लिए भोजन तक पहुंच और कठिन हो जाती है। यह स्थिति कुपोषण, गरीबी और सामाजिक अस्थिरता को जन्म देती है। कई क्षेत्रों में यह प्रवासन को भी बढ़ावा देती है, जहां लोग जीविका की तलाश में अपने घर छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। इस प्रकार, चरम गर्मी एक पर्यावरणीय समस्या से कहीं अधिक—एक व्यापक सामाजिक-आर्थिक संकट बन जाती है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए यह चुनौती और भी गंभीर है। हरियाणा, पंजाब और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में हाल के वर्षों में हीटवेव्स के कारण गेहूं और चावल की पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा गया है। विशेष रूप से देर से बोई गई फसलों पर इसका असर अधिक पड़ता है, जिससे उत्पादन में 10 से 15 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई है। भारत की हरित क्रांति का केंद्र रहे ये क्षेत्र अब जलवायु अस्थिरता के सबसे बड़े प्रयोगशाला बनते जा रहे हैं। इसके साथ ही, भूजल का अत्यधिक दोहन और बढ़ती गर्मी मिलकर जल संकट को और गहरा कर रहे हैं, जो कृषि की स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है।भारतीय संस्कृति ऐसे में समाधान की दिशा में ठोस और बहुआयामी रणनीतियों की आवश्यकता है। सबसे पहले, अनुकूलन (adaptation) पर ध्यान देना होगा। जलवायु-स्मार्ट कृषि पद्धतियां—जैसे गर्मी-सहनशील बीजों का उपयोग, फसल विविधीकरण, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई, तथा छायादार खेती—इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इसके अलावा, मौसम पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करना आवश्यक है, ताकि किसान समय रहते अपने निर्णय बदल सकें और नुकसान को कम कर सकें। पशुपालन के क्षेत्र में भी सुधार की आवश्यकता है। बेहतर वेंटिलेशन वाले शेड, पर्याप्त जल उपलब्धता और चयनात्मक प्रजनन जैसी तकनीकों के माध्यम से पशुओं को गर्मी के प्रभाव से बचाया जा सकता है। साथ ही, बीमा योजनाओं और वित्तीय सहायता के जरिए किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना भी आवश्यक है, ताकि वे जलवायु जोखिमों का सामना कर सकें। नीतिगत स्तर पर, सरकारों को एक समग्र और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। जल संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण और सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना प्राथमिकता होनी चाहिए। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और अन्य कृषि योजनाओं को जलवायु परिवर्तन के अनुरूप पुनर्गठित करने की आवश्यकता है। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग बढ़ाना और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना अनिवार्य है, क्योंकि दीर्घकालिक समाधान केवल शमन (mitigation) के माध्यम से ही संभव है। अंततः, यह समझना आवश्यक है कि चरम गर्मी का यह संकट एक चेतावनी है—एक ऐसा संकेत जो हमें बताता है कि हमारी विकास प्रणाली प्रकृति की सीमाओं से टकरा रही है। खाद्य प्रणालियों को सुरक्षित रखने के लिए हमें केवल तकनीकी और नीतिगत बदलाव ही नहीं, बल्कि अपने दृष्टिकोण में भी परिवर्तन लाना होगा। सततता, लचीलापन और समावेशिता को केंद्र में रखकर ही हम इस चुनौती का सामना कर सकते हैं।

बढ़ते तापमान और तीव्र होती हीटवेव्स ने कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य आपूर्ति शृंखलाओं को एक ऐसे दबाव में ला खड़ा किया है, जहां हर कड़ी कमजोर पड़ती दिख रही है। वैज्ञानिक और नीति-निर्माता अब इसे एक "रिस्क मल्टीप्लायर" के रूप में पहचान रहे हैं—ऐसा कारक जो न केवल स्वयं नुकसान पहुंचाता है, बल्कि अन्य जोखिमों को भी कई गुना बढ़ा देता है। यदि अब निर्णायक कदम नहीं उठाए गए, तो चरम गर्मी आने वाले दशकों में वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा व्यवस्थित खतरा बन जाएगी। चरम तापमान का सबसे प्रत्यक्ष और स्पष्ट प्रभाव फसलों पर पड़ता है। यह स्थापित तथ्य है कि 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान गेहूं, चावल और मक्का जैसी प्रमुख फसलों के लिए प्रतिकूल होता है। अधिक तापमान पौधों की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को बाधित करता है, परागण को प्रभावित करता है और दानों के विकास को अधूरा छोड़ देता है।

देश | दुनीया से

पर्यावरण संरक्षण राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न हिस्सा बने

भारत में मौसम का बदलता मिजाज और वैशाख के महीने में जेठ जैसी तपिश का अहसास होना अब केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि एक गहरे पारिस्थितिक संकट की चेतावनी है। अक्सर भीषण गर्मी और लू के लिए अल नीनो या वैश्विक जलवायु परिवर्तन को दोष देकर हम अपनी जिम्मेदारी से बचते रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह संकट काफी हद तक मानव-निर्मित है। आज हम जिस भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं, वह वैश्विक वायुमंडलीय बदलावों और स्थानीय स्तर पर पर्यावरण के प्रति बरती गई नीतिगत लापरवाही का एक मिला-जुला परिणाम है। जब हम अपनी विकास योजनाओं के नाम पर हजारों हेक्टेयर प्राथमिक जंगलों, पहाड़ियों और जल निकायों को नष्ट करते हैं, तो हम अनजाने में उन प्राकृतिक 'कूलिंग एजेंटों' को खत्म कर देते हैं जो इस तपिश के खिलाफ हमारी एकमात्र सुरक्षा थे। बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में, जहां तापमान अब नियमित रूप से 48 डिग्री सेल्सियस के स्तर को छूने लगा है, यह स्पष्ट है कि हमारी विकास की भूख ने धरती के प्राकृतिक थर्मोस्टेट को बिगाड़ दिया है। इस मानव-निर्मित गर्मी की सबसे प्रत्यक्ष और क्रूर मार उन मजदूरों और सड़क किनारे काम करने वाले श्रमिकों पर पड़ती है जो इस ढांचे का निर्माण कर रहे हैं। भारत के करोड़ों निर्माण श्रमिक, रेहड़ी-पटरी वाले और गिग-इकोनॉमी के कर्मचारी इस गर्मी को केवल एक आंकड़े के रूप में नहीं, बल्कि एक शारीरिक हमले के रूप में महसूस करते हैं। आंकड़ों के अनुसार, गर्मी के कारण भारत को 2030 तक अपने कुल कामकाजी घंटों का 5.8 प्रतिशत हिस्सा खोना पड़ सकता है, जो लगभग 3.4 करोड़ पूर्णकालिक नौकरियों के बराबर है। बांदा जैसे शहरों में, कंक्रीट और कोलतार की सड़कें गर्मी को सोखकर रात में भी उसे वापस छोड़ती हैं, जिससे 'अर्बन हीट आइलैंड' प्रभाव पैदा होता है और स्थानीय तापमान ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस तक अधिक बना रहता है।

नीतिगत स्तर पर मजदूरों के लिए 'छाया का अधिकार' या लू के दौरान काम के घंटों में बदलाव जैसे नियम केवल कागजों तक सीमित हैं, जो हमारे विकास के उस अंधेपन को दर्शाते हैं जहां श्रम को एक जैविक इकाई के बजाय केवल एक मशीन समझा जाता है। गर्मी का यह घातक रूप हमारी खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ रहा है। 'थर्मल शॉक' के कारण गेहूं जैसी प्रमुख फसलों के दाने दूध भरने की अवस्था में ही सूख रहे हैं, जिससे पैदावार में 15 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की जा रही है। मिट्टी की नमी खत्म होने से उपजाऊ जमीन अब मरुस्थल में बदल रही है, फिर भी हमारी नीतियां सूखे क्षेत्रों में अधिक पानी चाहने वाली फसलों को बढ़ावा दे रही हैं। इसी तरह, जंगलों के विखंडन और अवैध खनन ने वन्यजीवों के लिए भोजन का संकट पैदा कर दिया है। छतरपुर और पन्ना टाइगर रिजर्व के आसपास के इलाकों में, खनन के कारण प्राकृतिक जल स्रोत सूख चुके हैं, जिसके परिणामस्वरूप जंगली जानवरों का बस्तियों की ओर आना 40 प्रतिशत तक बढ़ गया है। यह केवल मानव-पशु संघर्ष नहीं है, बल्कि उस पारिस्थितिक सुरक्षा चक्र का टूटना है जो इंसानों और जानवरों को एक साथ सुरक्षित रखता था। वर्तमान 'हीट एक्शन प्लान' (एचएपी) की सबसे बड़ी विफलता यह है कि वे केवल शहरों में मौतों को रोकने पर केंद्रित हैं, जबकि जमीन, जल और मिट्टी के गिरते स्वास्थ्य की अनदेखी करते हैं। अब समय आ गया है कि नीतिगत स्तर पर 'वन हेल्थ' के दृष्टिकोण को अपनाया जाए, जहां मिट्टी की नमी, पशुधन का स्वास्थ्य और वन्यजीवों का संरक्षण एक ही इकाई के रूप में देखा जाए। हमें केवल पौधारोपण की रस्म अदायगी से ऊपर उठकर बुंदेलखंड के चंदेलकालीन तालाबों जैसे पारंपरिक जल-प्रबंधन तंत्र को पुनर्जीवित करना होगा। ये तालाब केवल पानी का स्रोत नहीं थे, बल्कि वे स्थानीय पारिस्थितिकी को ठंडा रखने के विकेंद्रीकृत साधन थे। नीति-निर्माताओं को यह समझना होगा कि राजमार्गों के लिए काटे गए पेड़ केवल लकड़ी नहीं थे, बल्कि वे उस सूक्ष्म-जलवायु का हिस्सा थे जो फसलों को झुलसने से बचाती थी। हमें विकास की अपनी परिभाषा को बदलना होगा। बुंदेलखंड में पत्थर खनन के लिए काटी गई हर पहाड़ी और उत्तराखंड में कंक्रीट के विस्तार के लिए नष्ट की गई हरियाली हमारे भविष्य की ठंडी हवाओं को रोक रही है। आर्थिक लाभ की तुलना में गर्मी के कारण होने वाला स्वास्थ्य और कृषि का नुकसान कहीं अधिक है। भविष्य की नीतियों की सफलता अब इस जवाबदेही पर टिकी है कि हम बुनियादी ढांचे के निर्माण में 'ग्रीन इंजीनियरिंग' को कितनी प्राथमिकता देते हैं और पर्यावरण नियमों की अनदेखी को कब बंद करते हैं। हमें यह स्वीकार करना होगा कि पर्यावरण का संरक्षण अब केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न हिस्सा है। तभी हम इस मानव-निर्मित भट्ठी से बाहर निकल पाएंगे और आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसी धरती दे पाएंगे जो केवल झुलसती नहीं, बल्कि जीवन भी प्रदान करती है।

आप का | नजरीया

जिंदगी निगलती रफ्तार

देश के नीति-नियंताओं की सोच रही है कि विकास के लिए चौड़ी व रफ्तार वाली सड़कें जीवन रेखा का काम करें। हाल के वर्षों में इसी सोच के साथ राजग सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण युद्ध स्तर पर किया। देश के उत्थान के लिए विकास के बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दी। लेकिन विकास की इस उन्नति के साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ी विसंगति भी सामने आई कि इन पर होने वाली दुर्घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। हादसों का यह सिलसिला लगातार जारी है। सवाल उठता है कि उच्च तकनीक से तैयार आकर्षक व सुविधाजनक एक्सप्रेस-वे और राष्ट्रीय राजमार्ग यात्रियों की सुरक्षा की कसौटी पर खरे क्यों नहीं उतर पा रहे हैं। यूं तो देश की कुल सड़कों में दो फीसदी ही राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, लेकिन देश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में इनकी संख्या तीस फीसदी हो गई है। जो हमारी गंभीर चिंता का सबब बन रहा है। ऐसे में आम नागरिकों की इस गहरी चिंता को महसूस करते हुए देश की शीर्ष अदालत ने हस्तक्षेप किया है। शीर्ष अदालत ने इस संकट पर गहरी चिंता जताते हुए केंद्र व राज्य सरकार तथा इससे संबधित विभागों को सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता के आधार पर सशक्त करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की मान्यता रही है अधिकारियों की उदासीनता व निर्माण से जुड़ी खामियों की वजह से राजमार्ग व एक्सप्रेस-वे दुर्घटना के कारक नहीं बनने चाहिए। इस दिशा में अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए ताकि मार्ग खतरे का गलियारा न बने। विडंबना यह भी है कि देश में आम लोगों में ट्रैफिक से जुड़ी अनुशासन की सोच पूरी तरह से विकसित नहीं हो पायी है। खुली सड़क मिलते ही रफ्तार तेज होने लगती है, यह जानते हुए कि ये गति हमारी दुर्गति का कारण भी बन सकती है। इसके अलावा तेज स्पीड में भी फोन पर बात करते रहना और शराब पीकर वाहन चलाना भी सड़क दुर्घटनाओं को बढ़ाने वाला साबित हुआ है। यह विडंबना ही है कि भारत में दुनिया के अन्य विकसित व समकक्ष विकासशील देशों के अनुपात में वाहनों की संख्या तो कम है लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में हम अव्वल हैं। यह आंकड़ा डराता है कि साल भर में होने वाली करीब साढ़े चार लाख से अधिक सड़क दुर्घटनाओं में हर साल डेढ़ लाख से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। इसके अलावा लाखों लोग घायल होते हैं। दुर्भाग्य से लाखों लोग ऐसे भी होते हैं जो जीवनपर्यंत अपंगता का शिकार हो जाते हैं। विडंबना यह भी कि सड़क दुर्घटनाओं में दम तोड़ने वाले लोगों में बड़ी संख्या युवा आबादी की है। ये युवा आबादी अपने परिवार की कमाई का मुख्य जरिया होती है, उनकी मौत पूरे परिवार को गरीबी की दलदल में धकेल देती है। यहां प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि तमाम सरकारी प्रयासों के बावजूद सड़क दुर्घटनाओं में कमी क्यों नहीं आ रही है। वास्तव में कोशिश होनी चाहिए कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए होने वाले प्रयास जमीनी हकीकत भी बनें, जो वास्तव में राजमार्गों व एक्सप्रेस-वे को दुर्घटनाओं से निरापद बना सकें। निस्संदेह, चौड़ी व तेज गति देने वाली सड़कें देश के विकास को प्राणवायु देती हैं, लेकिन ये सड़कें यात्रियों की प्राण रक्षा करने वाली भी होनी चाहिए। सरकार की तरफ से कोशिश होनी चाहिए कि राजमार्गों पर ढाबे एक निश्चित दूरी पर हों और उनके पास ट्रकों व भारी वाहनों को खड़ा करने का पर्याप्त स्थान हो। साथ ही अक्सर बड़ी दुर्घटना का कारण बनने वाले सड़क पर खड़े वाहनों पर रोक लगाने के लिए सख्त नियम बने और सख्त जुर्माना तय हो। कायदे से राजमार्गों पर कहीं भी वाहन को खड़ा करने की अनुमति प्रदान नहीं की जानी चाहिए। साथ ही सड़क निर्माण में किसी तकनीकी खामी की गुंजाइश न रहे, इसके लिये भी पर्याप्त सतर्कता उपाय किए जाने चाहिए। इन मार्गों पर अंधेरे में भी नजर आने वाले पर्याप्त संकेतक होने चाहिए ताकि वाहन चालकों को किसी तरह का असमंजस राजमार्ग पर चलते हुए न हो। वक्त आ गया है कि देश में दुर्घटनाओं को टालने के लिए आधुनिक यातायात प्रणाली के अनुसंधान व प्रयोग की दिशा में काम किया जाए।

देश के उत्थान के लिए विकास के बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दी। लेकिन विकास की इस उन्नति के साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ी विसंगति भी सामने आई कि इन पर होने वाली दुर्घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। हादसों का यह सिलसिला लगातार जारी है। सवाल उठता है कि उच्च तकनीक से तैयार आकर्षक व सुविधाजनक एक्सप्रेस-वे और राष्ट्रीय राजमार्ग यात्रियों की सुरक्षा की कसौटी पर खरे क्यों नहीं उतर पा रहे हैं। यूं तो देश की कुल सड़कों में दो फीसदी ही राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, लेकिन देश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में इनकी संख्या तीस फीसदी हो गई है। जो हमारी गंभीर चिंता का सबब बन रहा है। ऐसे में आम नागरिकों की इस गहरी चिंता को महसूस करते हुए देश की शीर्ष अदालत ने हस्तक्षेप किया है। शीर्ष अदालत ने इस संकट पर गहरी चिंता जताते हुए केंद्र व राज्य सरकार तथा इससे संबधित विभागों को सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता के आधार पर सशक्त करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की मान्यता रही है अधिकारियों की उदासीनता व निर्माण से जुड़ी खामियों की वजह से राजमार्ग व एक्सप्रेस-वे दुर्घटना के कारक नहीं बनने चाहिए। इस दिशा में अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए ताकि मार्ग खतरे का गलियारा न बने। विडंबना यह भी है कि देश में आम लोगों में ट्रैफिक से जुड़ी अनुशासन की सोच पूरी तरह से विकसित नहीं हो पायी है।

कुछ | अलग

अहंकार ने हमेशा परेशानी के सिवा कुछ नहीं दिया

बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक मूर्तिकार (मूर्ति बनाने वाला) रहता था। वह ऐसी मूर्तियां बनता था, जिन्हें देख कर हर किसी को मूर्तियों के जीवित होने का भ्रम हो जाता था। आस-पास के सभी गांव में उसकी प्रसिद्धि थी, लोग उसकी मूर्तिकला के कायल थे। इसीलिए उस मूर्तिकार को अपनी कला पर बड़ा घमंड था। जीवन के सफर में एक वक्ता ऐसा भी आया जब उसे लगने लगा कि अब उसकी मृत्यु होने वाली है, वह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। उसे जब लगा कि जल्दी ही उसकी मृत्यु होने वाली है तो वह परेशानी में पड़ गया। यमदूतों को भ्रमित करने के लिए उसने एक योजना बनाई। उसने हुबहू अपने जैसी दस मूर्तियां बनाई और खुद उन मूर्तियों के बीच जा कर बैठ गया। यमदूत जब उसे लेने आए तो एक जैसी ग्यारह आकृतियों को देखकर दंग रह गए। वे पहचान नहीं कर पा रहे थे कि उन मूर्तियों में से असली मनुष्य कौन है। वे सोचने लगे अब क्या किया जाए। अगर मूर्तिकार के प्राण नहीं ले सके तो सृष्टि का नियम टूट जाएगा और सत्य परखने के लिए मूर्तियों को तोड़ा गया तो कला का अपमान हो जाएगा। अचानक एक यमदूत को मानव स्वाभाव के सबसे बड़े दुर्गुण अहंकार को परखने का विचार आया। उसने मूर्तियों को देखते हुए कहा, कितनी सुन्दर मूर्तियां बनी हैं, लेकिन मूर्तियों में एक त्रुटी है। काश मूर्ति बनाने वाला मेरे सामने होता, तो मैं उसे बताता मूर्ति बनाने में क्या गलती हुई है। यह सुनकर मूर्तिकार का अहंकार जाग उठा, उसने सोचा, मेने अपना पूरा जीवन मूर्तियां बनाने में समर्पित कर दिया, भला मेरी मूर्तियों में क्या गलती हो सकती है? वह बोल उठा "कैसी त्रूटी"... झट से यमदूत ने उसे पकड़ लिया और कहा "बस यही गलती कर गए तुम अपने अहंकार में कि बेजान मूर्तियां बोला नहीं करती"।

दृष्टि | कोण

स्कूल की चौखट पर खड़ा बाजार, भीतर सिमटती शिक्षा

निजी विद्यालयों में एनसीईआरटी पुस्तकों के अनुपालन का सवाल अब महज पाठ्य सामग्री का विवाद नहीं रहा, बल्कि यह देश की शिक्षा व्यवस्था के चरित्र की परीक्षा बन चुका है। जब एक ओर कानून स्पष्ट दिशा देता हो और दूसरी ओर संस्थान स्वार्थवश उससे भटकें, तो यह केवल लापरवाही नहीं, बल्कि नैतिक विचलन का संकेत होता है। अप्रैल 2026 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा केंद्र, सीबीएसई और सभी राज्यों को जारी नोटिस ने इस विडंबना को उजागर किया है। यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या शिक्षा का अधिकार कानून केवल औपचारिक घोषणा बनकर रह गया है, या उसे लागू करने की प्रतिबद्धता ही क्षीण हो गई है। यह पूरा घटनाक्रम बताता है कि शिक्षा में समानता का मूल सिद्धांत निरंतर दबाव और उपेक्षा के बीच संघर्ष कर रहा है। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 की धारा 29 ने स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया था कि प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा 1 से 8) में पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों का निर्धारण एनसीईआरटी या संबंधित एससीईआरटी द्वारा किया जाएगा। इसी सोच के तहत एनसीईआरटी और एससीईआरटी को पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों के निर्धारण का अधिकार सौंपा गया। इन संस्थाओं द्वारा तैयार पुस्तकें न केवल शैक्षणिक रूप से संतुलित और विश्वसनीय होती हैं, बल्कि आम परिवारों के लिए किफायती भी रहती हैं। इसके विपरीत, निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें इस मूल उद्देश्य को कमजोर करती हैं। जब एक ही कक्षा की पुस्तकों पर हजारों रुपये खर्च होने लगें, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या शिक्षा अब अधिकार से ज्यादा एक लाभकारी व्यापार में बदलती जा रही है। निजी विद्यालयों में महंगी पुस्तकों को अनिवार्य बनाना कोई आकस्मिक भूल नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित आर्थिक तंत्र की ओर संकेत करता है। कई स्थानों पर स्कूल और प्रकाशक मिलकर ऐसा गठजोड़ रचते हैं, जिसमें शिक्षा का उद्देश्य पीछे छूट जाता है और मुनाफा केंद्र में आ जाता है। अभिभावकों को "उच्च गुणवत्ता" और "अधिक उपयोगी सामग्री" का

हवाला देकर इन पुस्तकों को खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है, जबकि इन दावों की ठोस पुष्टि प्रायः नहीं होती। इस पूरी प्रक्रिया में अभिभावकों की विवशता का व्यवस्थित दोहन होता है और वे विरोध करने में असहाय महसूस करते हैं। ऐसी प्रवृत्ति शिक्षा के नैतिक आधार को कमजोर करती है और संस्थागत विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े करती है। सबसे चिंताजनक परिणाम एक तेजी से गहराते शिक्षा-विभाजन के रूप में सामने आता है। जहां सरकारी विद्यालयों के बच्चे सस्ती, मानकीकृत और समान पुस्तकों से पढ़ते हैं, वहीं निजी स्कूलों के छात्र महंगी और अलग सामग्री पर निर्भर होते हैं, जिससे उनके ज्ञान का आधार ही भिन्न बन जाता है। यही अंतर आगे चलकर अवसरों की खाई को और चौड़ा कर देता है। मध्यम और निम्न वर्गीय परिवार पहले से ही शिक्षा पर बढ़ते खर्चों का दबाव झेल रहे हैं, ऐसे में किताबों का अतिरिक्त आर्थिक बोझ उनके लिए बेहद असहनीय हो जाता है। यह स्थिति केवल आर्थिक असमानता को नहीं बढ़ाती, बल्कि समाज में गहराते असंतुलन और विभाजन को भी और मजबूत करती है। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पहल एक महत्वपूर्ण और समयोचित हस्तक्षेप के रूप में सामने आती है, जिसने शिक्षा के अधिकार को मानवाधिकार के व्यापक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता को और स्पष्ट किया है। अनावश्यक तथा भारी-भरकम पुस्तकों का बढ़ता बोझ बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जो राष्ट्रीय स्कूल बैग पॉलिसी 2020 की मूल भावना के विपरीत है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री की पंजाब में ओबीसी को एकजुटता की अपील, अगली बार भाजपा की सरकार

चंडीगढ़ (हिंस)। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के ओबीसी समाज से आह्वान किया कि वे एकजुट हो जाएं तो अगले विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। भाजपा की सरकार सबको साथ लेकर चलती है, उसमें सभी वर्गों को बराबर प्रतिनिधित्व दिया जाता है। सैनी आज पंजाब के रूपनगर में ओबीसी समाज के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा दो दिन पहले *मजदूर दिवस* के अवसर पर बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने मजदूर दिवस पर मजदूरों का मजाक उड़ाया है जो कि उनकी गरीब विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले विधानसभा में भगवंत सिंह मान के व्यवहार की निंदा की। उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता ने पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत देकर जो विश्वास जताया था, सरकार के कारनामे देख कर आज वही जनता अपने आपको ठगा-सा महसूस कर रही है। विधानसभा में लाए गए विश्वास प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि उस दिन पंजाब के मुख्यमंत्री को यह भी बताना चाहिए था कि आम आदमी पार्टी ने गत चुनाव में किए गए कितने वायदों को पूरा किया है। नायब सिंह सैनी ने ओबीसी सम्मेलन में उमड़ी भारी भीड़ की तरफ मुखातिब होते हुए कहा कि यह सम्मेलन सामाजिक चेतना का एक विराट संगम है। इतनी बड़ी संख्या में इस समाज का यहां एकत्रित होना इस बात का संकेत है कि ओबीसी समाज अब अपने अधिकारों, अपने सम्मान और अपने भविष्य को लेकर जागरूक और संगठित हो चुका है। यह ऊर्जा, यह उत्साह और यह एकता आने वाले समय में एक नए सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन की नींव रखेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आगे कहा कि जब से देश की बागडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में आई है। तब से सामाजिक न्याय को केवल नारे के रूप में नहीं, बल्कि नीति और नियत दोनों के रूप में लागू किया गया है। प्रधानमंत्री स्वयं ओबीसी समाज से हैं। उन्होंने हमेशा समाज के वंचित, पिछड़े और गरीब वर्गों को मुख्यधारा में लाने का काम किया है। उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी समाज को केवल एक वोट बैंक के रूप में नहीं देखा, उसे नेतृत्व का अवसर देकर सशक्त बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उनके मंत्रिमंडल में 27 ओबीसी मंत्री हैं। आज देश के भाजपा शासित 5 राज्यों में ओबीसी समाज के मुख्यमंत्री हैं। यह पूरे ओबीसी समाज के गौरव और सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने ओबीसी समाज से एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने की अपील की और कहा कि आप सब मिलकर पार्टी को पंजाब में मजबूत बनाएं। आने वाले चुनाव को ध्यान में रखें और अभी से घर-घर भाजपा की अलख जगाएं। उन्होंने पंजाब की वर्तमान सरकार पर ओबीसी समाज के साथ अन्याय करने का आरोप लगाते हुए कहा कि हमें मिलकर इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी होगी तभी गरीब और पिछड़ा वर्ग को उसका हक मिलेगा। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद सरदार सतनाम सिंह संधू, पंजाब भाजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी शर्मा, भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, भाजपा नेता अनीस सिढाना, अजय वीर सिंह, परविंदर सिंह बराड़, दर्शन सिंह सैनी समेत अनेक वरिष्ठ नेता उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने ओड समाज को दी बड़ी सौगात, जयपुर में छात्रावास और रामदेवरा में धर्मशाला के लिए भूमि आवंटन की घोषणा

जयपुर (हिंस)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित ओड समाज संवाद कार्यक्रम में ओड समाज को बड़ी सौगात देते हुए जयपुर में छात्रावास तथा रामदेवरा में धर्मशाला निर्माण के लिए भूमि आवंटित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओड समाज का इतिहास श्रम, संस्कृति और स्वाभिमान का प्रतीक रहा है तथा राष्ट्र निर्माण में इस समाज का उल्लेखनीय योगदान रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओड समाज ने राजस्थान की जल संरक्षण परंपरा को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किलों, महलों और जल संरचनाओं के निर्माण में समाज की दक्षता ऐतिहासिक रही है। उन्होंने कहा कि समाज के पूर्वजों ने जल संसाधनों के संरक्षण और उपयोग की अद्भुत परंपरा विकसित की, जो आज भी प्रेरणास्रोत है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने पाक विस्थापित ओड समाज के लोगों की हरसंभव सहायता का आश्वासन देते हुए कहा कि राज्य सरकार उनके सामाजिक और शैक्षिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार द्वारा पेयजल और सिंचाई परियोजनाओं पर किए जा रहे कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है तथा ग्रामीण और श्रमिक वर्ग के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनकल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि महिलाओं, किसानों, श्रमिकों और वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कार्य कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों का सम्मान, सुरक्षा और सामाजिक संरक्षण सरकार की श्रम नीति का आधार है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, श्रम योगी मानधन योजना, ई-श्रम पोर्टल और श्रम-सेतु मोबाइल ऐप जैसी योजनाओं के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि, श्रमिक कल्याण योजनाओं के तहत करोड़ों रुपए के भुगतान, घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू समुदायों के लिए पट्टों के वितरण तथा शिक्षा सुविधाओं के विस्तार जैसे कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रत्येक जिले में घुमंतू एवं श्रमिक वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए *स्कूल ऑन व्हील्स* स्थापित किए जाएंगे। साथ ही पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, श्रमिक परिवारों को सामाजिक सहायता और बेटियों की शिक्षा व विवाह के लिए विशेष योजनाओं को भी सुदृढ़ किया जा रहा है।

विनेश फोगाट ने नेशनल ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट पर उठाए सवाल

चंडीगढ़ (हिंस)। उत्तर प्रदेश के गोंडा में होने वाले नेशनल ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट विवादों में घिर गए हैं। हरियाणा के उचाना हलके से विधायक एवं ओलंपियन विनेश फोगाट ने चेतावनी दी है कि अगर गोंडा में होने वाले आगामी नेशनल ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट के दौरान उन्हें या उनकी टीम के सदस्यों को कुछ भी अनहोनी होती है, तो इसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार होगी। टूर्नामेंट से पहले ही विनेश फोगाट ने पक्षपातपूर्ण अंपायरिंग को लेकर भी आशंकाएं जताईं। रविवार को फेसबुक पर एक वीडियो संदेश में फोगाट ने आरोप लगाया कि सीनियर ओपन रैंकिंग कुश्ती टूर्नामेंट अभी गोंडा में हो रहा है, जो बृज भूषण शरण सिंह का गढ़ है। उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि टूर्नामेंट के नतीजों पर भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख के करीबी लोगों का असर पड़ सकता है। विनेश ने कहा कि यह टूर्नामेंट ऐसी जगह आयोजित किया जा रहा है, जहां बृज का दबदबा बहुत ज़्यादा है। कौन किस मुकाबले में अंपायरिंग करेगा, कितने पॉइंट दिए जाएंगे,मैट चेयरमैन के तौर पर कौन बैठेगा। इन सभी चीजों को वह और उनके लोग अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। विनेश ने ऐसे माहौल में मुकाबला करने के मानसिक दबाव पर भी चिंता जताई है। यह चिंता इसलिए भी है,क्योंकि सिंह के खिलाफ चल रहे यौन उत्पीडन् के मामले में वह शिकायत करने वाली मुख्य लोगों में से एक हैं। पीड़ितों की पहचान और गरिमा की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए, फोगाट ने कहा कि हालात ऐसे बन गए थे कि उन्हें मजबूर होकर सबके सामने अपनी बात रखनी पड़ी। उन्होंने कहा कि मैं उन छह पीड़ितों में से एक हूं,जिन्होंने बृज भूषण शरण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अभी कोर्ट में मेरी गवाही चल रही है। ऐसे में उनके गढ़ में जाकर टूर्नामेंट में हिस्सा लेना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में किसी महिला के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाना बहुत मुश्किल होता है।

सैफई परिवार का 2047 तक मुख्यमंत्री बनने का सपना अधूरा ही रहेगा : केशव प्रसाद मौर्य

लखनऊ (हिंस)। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि, 2027 क्या, 2047 तक भी सैफई परिवार का मुख्यमंत्री बनने का सपना अधूरा ही रहेगा। केशव मौर्य ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा है कि सपा बहादुर अखिलेश यादव, आपके इशारों पर मर्यादा लांघकर *फर्जी पीडीए* परोसने वालों को उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता भली-भांति पहचानती है। सदन में आपकी भाषा और आचरण ही आपके समर्थकों की शैली और व्यवहार में साफ-साफ दिखाई पड़ते हैं और यही आपकी राजनीति की असल फितरत भी बेनकाब करते हैं। सपा का पूरा इतिहास अराजकता, जुल्म और गुंडागर्दी के काले पन्नों से भरा रहा है, जिसे प्रदेश की जनता अब दोबारा स्वीकार करने वाली नहीं है। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में फिर एक बार कमल खिलेगा और सुशासन कायम रहेगा।

मुख्यमंत्री योगी के हाथों नियुक्ति पत्र पाकर अभ्यर्थियों के खिले चेहरे, पारदर्शिता के लिए सरकार की सराहना की

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि में 357 और 252 दंत स्वास्थ्य विज्ञानियों को मिले नियुक्ति पत्र

लखनऊ (हिंस)। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के 357 कनिष्ठ विश्लेषक (औषधि) तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के 252 दंत स्वास्थ्य विज्ञानियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। मुख्यमंत्री के हाथों से नियुक्ति पत्र पाकर अभ्यर्थियों के चेहरे खुशी से दमक रहे थे। चयनित अभ्यर्थियों ने पारदर्शिता से भर्ती प्रक्रिया करने के लिए योगी सरकार की सराहना की। लोकभवन में आयोजित नियुक्त पत्र वितरण समारोह में कनिष्ठ विश्लेषक (औषधि) के पद पर चयनित औरैया के प्रतीक कुमार दीक्षित ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि समयबद्ध तरीके से चयन प्रक्रिया पूरी होना युवाओं के लिए बड़ी राहत है। प्रतीक ने यह भी कहा कि पहले प्रयोगशालाओं की संख्या कम थी, लेकिन योगी सरकार ने लैब बढ़ाकर रोजगार के नए अवसर सृजित किए हैं। दंत स्वास्थ्य विज्ञानी (डेंटल हाइजीनिस्ट) के पद पर चयनित लखनऊ की साक्षी सिंह ने नियुक्ति पत्र पाकर कहा कि यह पूरे परिवार के लिए गौरव का क्षण है। उन्होंने कहा कि पूरी चयन प्रक्रिया पारदर्शी रही, जिसके कारण योग्य अभ्यर्थियों को अवसर मिला है। मुख्यमंत्री के संबोधन से उन्हें प्रेरणा मिली है और वे अपने दायित्व का पूरी निष्ठा से निर्वहन करेंगी। दंत स्वास्थ्य विज्ञानी (डेंटल हाइजीनिस्ट) के पद पर चयनित कानपुर नगर की सभ्या कटियार ने कहा कि योगी सरकार में युवाओं को लगातार रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने इसे अपने जीवन का गौरवपूर्ण दिन बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के विचारों से प्रेरित होकर वे अपने पद की जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाएंगी। कनिष्ठ विश्लेषक औषधि के पद पर चयनित गाजीपुर के राकेश कुमार यादव ने कहा कि नियुक्ति पत्र पाकर मुझे बहुत खुशी है। भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हुई है। जो योग्य अभ्यर्थी हैं सिर्फ वही चयनित हुए हैं। राकेश ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने नया मुकाम हासिल करके पूरे देश में अग्रणी राज्य के रूप में स्थान बनाया है। कनिष्ठ विश्लेषक औषधि के पद पर चयनित मुरादाबाद की प्रियंका गौतम ने कहा कि मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार में सभी वर्गों, खासकर महिलाओं को सम्मान मिल रहा है। पहले जहां जानकारी तक नहीं मिल पाती थी, वहीं अब सरकार स्वयं बुलाकर सम्मान दे रही है। दंत स्वास्थ्य विज्ञानी (डेंटल हाइजीनिस्ट) के पद पर चयनित बस्ती के ऋषभ प्रताप सिंह और सीतापुर की पूजा वर्मा ने भी मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताते हुए कहा कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष रही और इससे युवाओं का भरोसा मजबूत हुआ है। कार्यक्रम के दौरान अभ्यर्थियों ने एक स्वर में कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने देश में एक नई पहचान बनाई है।

सरहद पार के हथियार तस्करी मॉड्यूल से जुड़े चार गुर्गे गिरफ्तार, सात पिस्तौलें बरामद

चंडीगढ़(हिंस)। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने चार हथियार तस्करों को गिरफ्तार करके सरहद पार से हथियारों की तस्करी के एक और मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इनके पास से ऑस्ट्रिया निर्मित दो 9 एमएम ग्लॉक, चीन निर्मित चार .30 बोर और एक .30 बोर पिस्तौल बरामद की गई हैं। पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने रविवार को बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान समरबीर सिंह उर्फ सिमर (21) निवासी महिंद्रा कॉलोनी, अमृतसर; सतनाम सिंह उर्फ सत्ता (23) निवासी गांव फतेहपुर, तरनतारन, तनुप्रीत सिंह (26) निवासी प्रताप नगर, अमृतसर और करनजोत सिंह उर्फ साजन (26) निवासी कृष्णा नगर, अमृतसर के रूप में हुई है। इनके पास से बरामद किए गए हथियारों में ऑस्ट्रिया निर्मित दो 9 एमएम ग्लॉक, चीन निर्मित चार .30 बोर और एक .30 बोर पिस्तौल हैं। डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि प्रारंभिक जांच के अनुसार गिरफ्तार किए गए हथियार तस्कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से पाकिस्तान स्थित तस्करों के संपर्क में थे। उन्होंने बताया कि गैर-कानूनी हथियारों की खेप सरहद पार से ड्रोन के जरिए भेजी गई थी, जिसे स्थानीय सहयोगियों के माध्यम से आगे आपराधिक तत्वों में वितरित किया जा रहा था। पुलिस आयुक्त (सीपी) अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर एक योजनाबद्ध कार्रवाई में समरबीर उर्फ सिमर को दो ग्लॉक पिस्तौलों सहित गिरफ्तार किया गया था। उससे पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई में उसके तीन अन्य साथियों सतनाम उर्फ सत्ता, तनुप्रीत सिंह और करनजोत उर्फ साजन को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके खुलासों के आधार पर पांच और पिस्तौल बरामद की गईं। पुलिस आयुक्त ने बताया कि सतनाम उर्फ सत्ता पहले भी व्यावसायिक मात्रा में हेरोइन की बरामदगी से संबंधित एक मामले में शामिल रहा है और उसके कब्जे से 8 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई थी। उन्होंने आगे बताया कि सतनाम सत्ता और करनजोत उर्फ साजन एक ही मोहल्ले में रहते हैं और पाकिस्तान-आधारित हैंडलर के निर्देशों पर मिलकर काम कर रहे थे।

कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़े, अब 3389 में मिल रहा

सुपौल (हिंस)। जिले के उपभोक्ताओं को शनिवार से 3389 रुपए में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति की जा रही है। जबकि शुक्रवार तक यह सिलेंडर 2395 रुपए में मिल रहा था। केंद्र सरकर ने शुक्रवार की रात से प्रति कामर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 993 रुपए की वृद्धि कर दी है। कारोबारियों का कहना है कि उन्हें पहले से अंदेशा था कि विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद गैस की कीमत में वृद्धि हो सकती है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच सरकार ने 1 मई से 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 993 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। शहर के मिंटू कुमार कहते हैं कि इसका असर सिर्फ आमजनों के खाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कई जरूरी चीजें महंगी हो सकती हैं। होटल, रेस्तरां, कैटरिंग, फूड बिजनेस, सरकारी संस्थाओं के किचन और छोटे कारोबारों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। कामर्शियल एलपीजी का इस्तेमाल होटल, रेस्तरां, चाय-समोसा की दुकानें, कैटरिंग सर्विस और फूड बिजनेस में होता है। बड़ी कीमत का असर खाने-पीने के कारोबार पर पड़ेगा। रेस्तरां और होटल में खाने की कीमत में 10-15 प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है। कीमत बढ़ने से उनका प्रॉफिट मार्जिन और कम हो जाएगा। अब इस नई बढ़ोतरी से रेस्तरां फूड और होटल फूड और महंगा हो सकता है। विक्रेता मुकेश हलुवाई ने बताया कि अगर खाने-पीने की चीजों की कीमत में वृद्धि करेंगे या मेन्यू में कटौती करेंगे तो ग्राहकों की आवाजाही कम होगी। ऐसे में आय पर दबाव पड़ेगा। इन दिनों लग्न का मौसम चल रहा है, लेकिन कामर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। जिन परिवारों में शादी या तिलक समारोह है, उनके लिए खर्च संभालना मुश्किल हो रहा है। युगल चौक के पास खरीदारी कर रही चिंता देवी और ममता देवी ने बताया कि उनकी बेटियों की शादी सात और आठ मई को है।

गुरुग्राम में जनगणना कार्य में अनुपस्थित कर्मचारी नपेंगें, अब होगी निगरानी

गुरुग्राम (हिंस)। जनगणना के कार्य में 500 से अधिक सुपरवाइजर एवं एन्यूमरेटर ड्यूटी और प्रशिक्षण से अनुपस्थित पाए गए हैं। नगर निगम की ओर से सख्त निर्णय लिया गया कि ऐसे कर्मचारियों को नोटिस जारी किए जाएंगे। निर्धारित समय में जवाब नहीं देने पर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह बात प्रधान जनगणना अधिकारी एवं निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने रविवार को नगर निगम गुरुग्राम में जनगणना कार्यों की प्रगति को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक में कही। इस बैठक में विभिन्न अधिकारियों की उपस्थिति में जनगणना कार्यों को गति देने, अनुपस्थित कर्मचारियों पर कार्रवाई तथा निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए गए। बैठक में सभी विभागों और संस्थानों को निर्देशित किया गया कि उनके अधीनस्थ कर्मचारी तुरंत जनगणना कार्य में शामिल हों। साथ ही अनुपस्थित सुपरवाइजर और एन्यूमरेटर को पांच मई से सात मई 2026 तक प्रशिक्षण में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। अनुपालन न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जनगणना कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनुपस्थिति या उदासीनता को गंभीरता से लिया जाएगा और दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी अधिकारियों को अपने स्टाफ की नियमित निगरानी और कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में जनगणना कार्यों को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए गए, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि गुरुग्राम में जनगणना प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी तरीके से सम्पन्न हो। साथ ही निगम पार्षदों, आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों व नागरिकों से अपील की गई कि वे जनगणना कार्य में सहयोग करें। जनगणना कार्यों की निगरानी और समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक जोन स्तर पर जोनल ग्रीवेंस सेल गठित करने का निर्णय लिया गया। ये सेल प्रतिदिन कार्यों की समीक्षा करेंगे, प्रत्येक गुरुवार को फील्ड निरीक्षण करेंगे तथा हर शुक्रवार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा, निगमायुक्त कार्यालय में सेन्सस मैनेजमेंट सेल गठित किया गया है, जिसकी अध्यक्षता निगमायुक्त स्वयं करेंगे। यह सेल जनगणना कार्यों की निगरानी, शिकायतों के समाधान तथा आवश्यक समन्वय सुनिश्चित करेगा। बैठक में जानकारी दी गई कि कुछ जोन में जनगणना किट वितरित कर दी गई हैं, जबकि अन्य जोनों में उसी दिन वितरण पूरा करने के निर्देश दिए गए। साथ ही, प्रशिक्षण से अनुपस्थित एमसीजी कर्मचारियों की समीक्षा कर उनकी अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा गया।

अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पत्रकारों को दी बधाई

पटना (हिंस)। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पत्रकारों को बधाई दी है।सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। पोस्ट के साथ उन्होंने पत्रकारों को शुभकामनाएं देने वाली एक तस्वीर भी साझा की है। पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है-
अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी पत्रकार बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं।
लोकतंत्र की मजबूती में स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।
आपकी कलम सच्चाई, पारदर्शिता और जनहित की आवाज बनकर समाज को जागरूक करती रहे, साथ ही आपकी जनहित के प्रति सदैव प्रतिबद्धता बनी रहे, इसी विश्वास के साथ आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।

विश्वमांगल्य सभा का प्रांतीय अधिवेशन आयोजित *मातृत्व संस्कार समागम* में युगानुकूल मातृत्व पर हुआ मंथन

जयपुर (हिंस)। विश्वमांगल्य सभा प्रांत जयपुर द्वारा रविवार को इंदिरा गांधी पंचायतराज एंड रूरल डपलपमेंट इंस्टीटयूट में प्रांतीय अधिवेशन *मातृत्व संस्कार समागम - परंपरा, प्रगति एवं परिपक्वता का संगम* का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मातृत्व की भूमिका, परिवार निर्माण और राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की केंद्रीय भागीदारी पर व्यापक चिंतन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राज्य मंत्री मंजू बाघमार रहीं, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा महिला मोर्चा राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष राखी राठौड़ ने की। साथ ही विश्वमांगल्य सभा की राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉ. वृषाली जोशी तथा राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका शुक्ला ने भी अधिवेशन को संबोधित किया। विश्वमांगल्य सभा जयपुर प्रांत की अध्यक्ष सुनीता राजोरिया ने बताया कि विश्वमांगल्य सभा एक राष्ट्रव्यापी संगठन है, जिसकी स्थापना 19 जनवरी 2010 को नागपुर में आचार्य जितेन्द्र नाथ की प्रेरणा से हुई थी। संगठन का उद्देश्य प्रत्येक परिवार की मातृशक्ति को केंद्र में रखते हुए संस्कारित, सक्षम और नैतिक समाज का निर्माण करना है। अधिवेशन का मुख्य विषय *युगानुकूल मातृत्व पर चिंतन* रहा। राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉ. वृषाली जोशी ने अपने प्रेरक उद्बोधन में कहा कि संगठन के कार्य का मूल केंद्र *मां* है। उन्होंने मां जीजाबाई, सारदा देवी, रानी लक्ष्मीबाई और पन्नाधाय जैसी महान मातृशक्तियों के आदर्शों का उल्लेख करते हुए कहा कि मातृत्व केवल परिवार तक सीमित नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने बताया कि विश्वमांगल्य सभा मातृशक्ति के चार प्रमुख स्तंभ संस्कार, सामर्थ्य, सेवा और सदाचार पर विशेष रूप से कार्य कर रही है। संगठन का लक्ष्य प्रत्येक घर में ऐसी माताओं का निर्माण करना है, जो अपने परिवार को नैतिक मूल्यों, संस्कारों और दूरदर्शिता से नेतृत्व प्रदान कर सकें। कार्यक्रम के दौरान समाज के विभिन्न क्षेत्रों जैसे ज्ञान, कला, उद्यम, सेवा, शक्ति, मातृत्व और धर्म में उल्लेखनीय योगदान देने वाली सात विशिष्ट माताओं का सम्मान भी किया गया। इस सम्मान समारोह ने कार्यक्रम को प्रेरणा और सामाजिक जागरूकता का विशेष आयाम प्रदान किया।

टाटा संस पर शेयर बाजार में लिस्टिंग को लेकर चौतरफा दबाव

प्राक्सी एडवाइजरी ने आरबीआई से लिस्टिंग के निर्देश जारी करने का किया आग्रह

मुंबई

टाटा की होल्डिंग कंपनी टाटा संस पर शेयर बाजार में लिस्टिंग को लेकर चौतरफा दबाव बन रहा है। इसी कड़ी में अब प्राक्सी एडवाइजरी या संस्थागत निवेशकों को सलाह देने वाली कंपनी इनगवर्न रिसर्च सर्विसेज ने आरबीआई से आग्रह किया है कि वह टाटा संस की लिस्टिंग को लेकर निर्देश जारी करे।

इनगवर्न रिसर्च सर्विसेज ने कहा कि हाई लेयर वाली एनबीएफसी के रूप में मार्च 2027 तक सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। एक रिपोर्ट में कहा है कि मौजूदा नियामकीय आउटलुक में इतने बड़े संस्थान को लिस्टिंग से छूट देने का कोई कानूनी आधार नहीं बचा है।

इसके साथ ही सलाहकार फर्म ने यह मांग भी रखी है कि टाटा संस द्वारा प्रमुख निवेश कंपनी के रूप में रजिस्ट्रेशन समाप्त करने के आवेदन को आरबीआई औपचारिक रूप से खारिज कर दे। बता दें कि टाटा संस ने मार्च 2024 में यह आवेदन दायर किया था, जिसे फर्म ने सार्वजनिक सूचीबद्धता से बचने की एक कोशिश बताया।

रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में जारी संशोधित नियामकीय दिशा-निर्देशों के बाद यह आवेदन प्रक्रियात्मक और वास्तविक रूप से अप्रासंगिक हो गया है। फर्म ने कहा कि स्किल-आधारित नियमन स्ट्रक्चर के तहत अनिवार्य सूचीबद्धता से बचने का प्रयास मौजूदा वित्तीय निगरानी मानकों के अनुरूप नहीं है।

फर्म ने कहा कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के सूचीबद्धता नियम समूह स्तर पर संबंधित पक्षों में लेनदेन और पूंजी आवंटन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी हैं। खासकर टाटा संस के तहत टीसीएस, टाटा मोटर्स और टाटा पावर जैसी बड़ी सूचीबद्ध कंपनियों के आने से यह जरूरी है।

रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई को मार्च 2024 के आवेदन को खारिज करते हुए स्पष्ट आदेश जारी करना चाहिए ताकि एसबीआर स्ट्रक्चर की विश्वसनीयता बनी रहे और टाटा समूह में निवेश करने वाले करोड़ों निवेशकों के हितों की रक्षा हो सके।

फर्म ने यह भी कहा कि अप्रैल 2026 के ड्राफ्ट दिशा-निर्देशों के तहत एक लाख करोड़ रुपए की एसेट लिमिट को हाई लेयर वाली एनबीएफसी के रूप में वर्गीकरण के लिए मानक बनाया जाना चाहिए। इस आधार पर टाटा संस अपने आकार के कारण स्वत: ही इस श्रेणी में आ जाती है। हालांकि, टाटा संस की ओर से इस मामले पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। बता दें टाटा की होल्डिंग कंपनी टाटा संस करीब 1.75 लाख करोड़ की एसेट्स को नियंत्रित करती है।

न्यूज़ ब्रीफ

आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने रोहित जैन, अनुभवी अधिकारी टी रबी शंकर का स्थान लेंगे

नई दिल्ली। सरकार ने रोहित जैन को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। उन्हें तीन साल के कार्यकाल के लिए यह अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। जैन, टी रबी शंकर का स्थान लेंगे, जिनका विस्तारित कार्यकाल हाल ही में समाप्त हुआ है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने तीन मई या उसके बाद पदभार ग्रहण करने की तारीख से रोहित जैन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसार केंद्रीय बैंक में चार डिप्टी गवर्नर होने चाहिए। रोहित जैन के साथ अब स्वामीनाथन जे, पूनम गुप्ता और एस सी मुर्मू अन्य तीन डिप्टी गवर्नर होंगे। जैन का पदभार संभालना टी रबी शंकर के विस्तारित कार्यकाल की समाप्ति के बाद हुआ है, जिन्हें सितंबर 2021 में नियुक्त किया गया था और बाद में उनके कार्यकाल को 2024 और फिर 2025 तक बढ़ाया गया था। रोहित जैन एक अनुभवी अधिकारी हैं और इससे पहले आरबीआई में कार्यकारी निदेशक के पद पर कार्यरत थे। उनके पास केंद्रीय बैंकिंग, विदेशी मुद्रा प्रबंधन और वित्तीय स्थिरता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों का व्यापक अनुभव है। उनकी नियुक्ति ऐसे महत्वपूर्ण समय में हुई है जब आरबीआई के समक्ष वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखने और बढ़ती मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाने जैसी प्रमुख चुनौतियां हैं।

कोटक महिंद्रा बैंक का मुनाफा 10 फीसदी उछला

नई दिल्ली। बैंकिंग सेक्टर की दिग्गज कंपनी कोटक महिंद्रा बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही के नतीजे पेश कर दिए हैं। जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक बैंक ने अपने मुनाफे में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की है। बैंक का समेकित मुनाफा सालाना आधार पर 10 प्रतिशत बढ़कर 5,423 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। अगर सिर्फ स्टैंडअलोन आधार पर बात करें तो बैंक के मुनाफे में 13 फीसदी का उछाल आया है, जो अब 4,027 करोड़ रुपये हो गया है। पिछले साल इसी तिमाही में यह आंकड़ा 3,552 करोड़ रुपये था। बैंक की इस कामयाबी के पीछे प्रोविजनिंग में आई भारी कमी और एसेट क्वालिटी का बेहतर होना मुख्य वजह मानी जा रही है। बैंक की ब्याज से होने वाली शुद्ध आय में भी सुधार देखा गया है। सालाना आधार पर इसमें 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 7,876 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। हालांकि, अन्य आय के मामले में बैंक को मामूली गिरावट झेलनी पड़ी, जो 2 प्रतिशत घटकर 3,116 करोड़ रुपये रह गई।

एलपीजी की महंगाई का झटका, दिल्ली के खाने का स्वाद होगा महंगा,

नई दिल्ली। दिल्ली के लजीज पकवानों का स्वाद अब महंगा होने वाला है। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में हुई रिकार्ड 50 प्रतिशत की वृद्धि ने शहर के होटल और रेस्टोरेंट उद्योग को गहरे संकट में डाल दिया है। इस अप्रत्याशित बढ़ोतरी के चलते कारोबारियों ने मेन्यू कार्ड के दाम बढ़ाने की चेतावनी दी है, जिससे आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। राजधानी के खाद्य व्यापार पर इस वक्त एक तरह का आर्थिक शाक लगा है, जिसने तंदूर की आंच से ज्यादा व्यापारियों के माथे पर चिंता की लकीरें गरम कर दी हैं। 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में एक ही बार में 993 रुपये का इजाफा हुआ है, यह बीते तीन महीनों में तीसरी बढ़ोतरी है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता इसका मुख्य कारण है। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन आफ इंडिया का कहना है कि उद्योग पहले से ही बढ़ती लागत से जूझ रहा था, ऊपर से इस भारी इजाफे ने कमर तोड़ दी है। उन्होंने बताया कि बाजार में गैस सिलेंडरों की भारी कमी और कालाबाजारी की खबरें हैं। जो सिलेंडर पहले 1,300-1,600 रुपये में मिलते थे, अब खुले बाजार में 3,000-4,000 रुपये में बिक रहे हैं। एक मध्यम आकार का रेस्टोरेंट प्रतिदिन 2 से 5 सिलेंडर का उपयोग करता है, जिससे दैनिक परिचालन लागत हजारों रुपये बढ़ गई है। यदि यही स्थिति बनी रही, तो छोटे ढाबे और रेस्टोरेंट बंद होने के कगार पर होंगे, साथ ही बड़े पैमाने पर छंटनी का खतरा भी है।

चार नई इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड एसयूवी लान्च करेंगी ये कंपनी

नई दिल्ली

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर अब नए प्रोडक्ट्स के जरिए ग्राहकों को आकर्षित करने की बड़ी तैयारी में जुट गई है। आने वाले समय में कंपनी भारतीय बाजार में चार नई इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड एसयूवी लान्च करने की योजना बना रही है। इन अपकमिंग माडलों में एमजी आईएम6, एमजी स्टारलाइट 560, एमजी एस5 और एमजी स्टारलाइट 560 ईवी शामिल हैं।

कंपनी का फोकस तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन सेगमेंट में अपनी पकड़ को और मजबूत करना है। एमजी आईएम6 को प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी के तौर पर पेश किया जाएगा। इसकी सीधी टक्कर हुंडई आयोनिक 5, किआ ईवी6 जीटी, बीवाईडी सीलायन 7 और टेस्ला माडल वाई जैसी गाड़ियों से मानी जा रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध इसके रियर व्हील ड्राइव माडल में सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जो 408 बीएचपी की ताकत पैदा करती है। वहीं इसका आल व्हील ड्राइव वेरिएंट 778 बीएचपी तक की पावर और दमदार परफार्मेंस देने में सक्षम है। कंपनी की दूसरी महत्वपूर्ण पेशकश एमजी स्टारलाइट 560 होगी, जो भारत में कंपनी की पहली प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी बन सकती है। इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 20.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक दिया जाएगा।

रिपोर्ट्स के मुताबिक यह माडल भारत में सात सीटर विकल्प के रूप में लान्च किया जा सकता है, जिससे यह फैमिली एसयूवी सेगमेंट में मजबूत दावेदारी पेश करेगी। वहीं एमजी एस5 इलेक्ट्रिक एसयूवी मौजूदा जेडएस ईवी की जगह ले सकती है। दूसरी ओर एमजी स्टारलाइट 560 ईवी को प्योर इलेक्ट्रिक माडल के रूप में पेश किया जाएगा। इसमें 56.7 किलोवाट आवर बैटरी पैक मिलने की संभावना है, जो फुल चार्ज पर लगभग 500 किलोमीटर तक की रेंज देने में सक्षम होगी। इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस ऐपल कारप्ले, एंड्रायड आटो और कई आधुनिक फीचर्स मिलने की उम्मीद है।

एथर नए इलेक्ट्रिक स्कूटर लांच करने की तैयारी में

नई दिल्ली। एथर एनर्जी अब कम कीमत वाले नए इलेक्ट्रिक स्कूटर लांच करने की तैयारी में जुट गई है। पिछले कुछ वर्षों में एथर कंपनी ने बिक्री के मामले में लगातार शानदार प्रदर्शन किया है। खासतौर पर रिज्टा स्कूटर लॉन्च होने के बाद एथर की बिक्री में बड़ी तेजी देखने को मिली है। अब कंपनी अपने नए ईएल प्लेटफार्म पर आधारित पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर को बाजार में उतारने की तैयारी कर रही है। हाल ही में इस नए स्कूटर को टेस्टिंग के दौरान देखा गया, जिसके बाद इसे लेकर बाजार में चर्चाएं तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि यह माडल कम कीमत वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में बड़ा बदलाव ला सकता है। एथर ने अपने ईएल प्लेटफार्म की पहली झलक कम्युनिटी डे 2025 के दौरान दिखाई थी। कंपनी ने इस प्लेटफार्म को माड्यूलर और अफार्डेबल तरीके से तैयार किया है, ताकि एक ही प्लेटफार्म पर अलग-अलग बैटरी क्षमता और फीचर्स वाले कई माडल विकसित किए जा सकें। रिपोर्ट्स के अनुसार इस प्लेटफार्म पर आधारित स्कूटरों में 2 किलोवाट आवर से लेकर 5 किलोवाट आवर तक के बैटरी विकल्प मिल सकते हैं। इसके अलावा लागत कम रखने और बेहतर टिकाऊपन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी एलएफपी बैटरी तकनीक का इस्तेमाल भी कर सकती है। बताया जा रहा है कि शुरुआती माडल में बेसिक फीचर्स पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, जबकि इसके महंगे वेरिएंट में टीएफटी डिस्प्ले, स्मार्ट कनेक्टिविटी, एडवांस राइडिंग मोड और अन्य आधुनिक फीचर्स देखने को मिल सकते हैं।

एनपीएस में बड़ा बदलाव, जुलाई 2026 से जेब पर बढ़ेगा बोझ

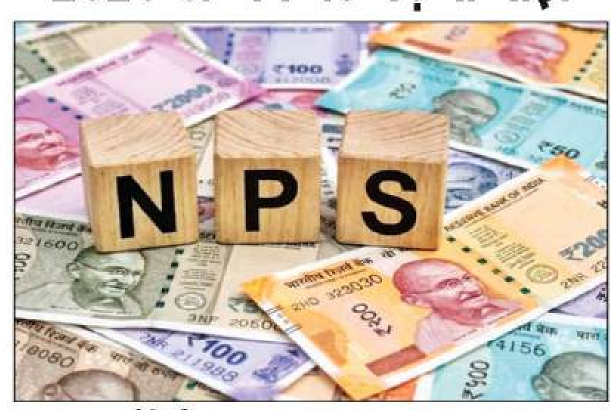

नई दिल्ली

नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में निवेश करने वाले करोड़ों सब्सक्राइबर्स के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। पेंशन फंड रेगुलेटर पीएफआरडीए ने एनपीएस खातों पर लगने वाले सालाना मेंटेनेंस चार्ज (एएमसी) में बदलाव की घोषणा की है, जो जुलाई 2026 से लागू होंगे। 29 अप्रैल को जारी इस सर्कुलर का मकसद शुल्कों में एकरूपता लाना और मौजूदा विसंगतियों को दूर करना है।

टियर-2, डार्मेंट खातों और विभिन्न निवेश स्कीम्स पर पड़ेगा सीधा असर

इन नए नियमों का सीधा असर आपके टियर-1, टियर-2 और निष्क्रिय (डार्मेंट) खातों पर पड़ेगा, जिससे आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग की लागत में बदलाव आ सकता है। टियर-1 और टियर-2 खाते हुए बराबर एनपीएस सब्सक्राइबर्स के लिए एक अहम बदलाव टियर-2 खातों से संबंधित है। अब तक टियर-1 और टियर-2 खातों के मेंटेनेंस चार्जेस में अंतर था, लेकिन पीएफआरडीए ने अब इन्हें एक समान कर दिया है। इसका अर्थ है कि टियर-2 खाते पर भी वही सालाना मेंटेनेंस चार्ज लगेगा जो उसी सेक्टर के टियर-1 खाते पर लागू होता है। यह उन निवेशकों के लिए मायने रखता है जो टियर-2 को बचत के एक लचीले विकल्प के तौर पर देखते थे, क्योंकि अब इसकी लागत बढ़ जाएगी। हालांकि, छोटे निवेशकों को राहत देते हुए, अगर किसी तिमाही के अंत में टियर-2 खाते का बैलेंस 1,000 रुपये या उससे कम है, तो कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं लिया जाएगा। हर स्कीम पर अलग चार्ज इसके अलावा पीएफआरडीए ने स्पष्ट किया है कि एक ही पीआरएएन (परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर) के तहत हर पेंशन स्कीम को अब एक अलग खाता माना जाएगा। इसका मतलब है कि यदि आपने इक्विटी, कार्पोरेट बान्ड और सरकारी सिक्योरिटी जैसी विभिन्न स्कीम्स में पैसा लगाया है, तो हर स्कीम पर अलग से मेंटेनेंस चार्ज लग सकता है।

यूएई ने अपने हवाई क्षेत्र में सामान्य उड़ान संचालन बहाल किया

नई दिल्ली। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने अपने हवाई क्षेत्र में सामान्य उड़ान संचालन को पूरी तरह बहाल करने की घोषणा की है। देश के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (जीसीएए) ने बताया कि सुरक्षा और परिचालन स्थिति की विस्तृत समीक्षा के बाद यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पहले एहतियातन उठाए गए कुछ कदमों को अब हटा लिया गया है। जीसीएए ने एयरस्पेस की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार रियल-टाइम निगरानी जारी रखने का आश्वासन दिया है। इसके लिए तकनीकी और आपरेशनल टीमें पूरी तरह तैयार हैं, ताकि किसी भी नई स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। प्राधिकरण ने इस दौरान यात्रियों और एयरलाइंस के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया और लोगों को जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करने की सलाह दी है।

बीमा क्षेत्र में अब 100 फीसदी विदेशी मालिकाना हक

आटोमैटिक रूट से होगा निवेश, लेकिन आईआरडीएआई की मंजूरी अनिवार्य

नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने भारतीय बीमा क्षेत्र को विदेशी निवेश के लिए पूरी तरह खोल दिया है। एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए वित्त मंत्रालय ने हाल ही में अधिसूचना जारी कर बीमा कंपनियों में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दे दी है। यह निवेश आटोमैटिक रूट के तहत होगा, जिससे विदेशी कंपनियां बिना पूर्व सरकारी मंजूरी के भारतीय बीमा कंपनियों में पूर्ण हिस्सेदारी ले सकेंगी। इससे पहले बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की अधिकतम सीमा 74 प्रतिशत थी, जिसे अब बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से विदेशी निवेशकों के लिए भारत का बीमा बाजार और अधिक आकर्षक बन गया है। हालांकि, इस फैसले के बावजूद बीमा नियामक संस्था आइआरडीएआई (भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण) की मंजूरी और जांच अनिवार्य रहेगी। यह महत्वपूर्ण बदलाव सबका बीमा, सबकी रक्षा विधेयक 2025 के तहत किया गया है, जिसे दिसंबर 2025 में संसद की मंजूरी और राष्ट्रपति की सहमति मिल चुकी थी। इस अधिसूचना के बाद अब विदेशी संस्थाएं और पोर्टफोलियो निवेशक भारत की बीमा कंपनियों में शत-प्रतिशत हिस्सेदारी तक निवेश कर सकेंगे। सरकार का यह निर्णय बीमा कंपनियों को विस्तार के लिए अधिक पूंजी और संसाधन जुटाने में मदद करेगा। इससे नई तकनीकों, उत्पादों और सेवाओं को अपनाने में तेजी आएगी, जिससे भारतीय बीमा बाजार अधिक प्रतिस्पर्धी और विकसित होगा। हालांकि, सरकार ने एक महत्वपूर्ण शर्त भी जोड़ी है: जिन बीमा कंपनियों में शत-प्रतिशत विदेशी निवेश होगा, उनमें कम से कम एक शीर्ष पद पर भारतीय नागरिक का होना अनिवार्य होगा।

वीवो की अनोखा फीचर शेक एंड शेयर लाने की तैयारी

नई दिल्ली

वीवो स्मार्टफोन कंपनी एक नया और अनोखा फीचर शेक एंड शेयर लाने की तैयारी कर रही है। इस फीचर में आपको बस अपना फोन हल्का सा हिलाना होगा और फोटो, वीडियो या डाक्यूमेंट जैसी फाइलें ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगी। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह फीचर अभी डेवलपमेंट स्टेज में है और इसे आने वाले अपडेट्स में पेश किया जा सकता है, जो फाइल शेयरिंग के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। वीवो का यह शेक एंड शेयर फीचर फोन के अंदर मौजूद मोशन सेंसर और वायरलेस टेक्नोलाजी का स्मार्ट तरीके से उपयोग करेगा।

जब आप अपने फोन को हिलाते हैं, तो यह मूवमेंट को पहचान कर आसपास के अन्य कम्पैटिबल वीवो डिवाइसों को खोजना शुरू कर देता है। जैसे ही कोई डिवाइस मिलता है, दोनों फोन के बीच एक सुरक्षित कनेक्शन बनता है और आपकी चुनी हुई फाइल तुरंत ट्रांसफर होने लगती है।

इसमें वाई-फाई डायरेक्ट जैसी तेज टेक्नोलाजी का इस्तेमाल होगा, जिससे फाइल ट्रांसफर की गति भी काफी अच्छी मिलेगी। यह बेहद आसान और तेज प्रक्रिया है, जिससे फाइल शेयरिंग काल करने या मैसेज भेजने जितनी ही सहज हो जाएगी। यह फीचर फिलहाल केवल वीवो एक्स300 अल्ट्रा और एक्स300 एफई के लिए ही उपलब्ध होगा, जिन्हें 6 मई, 2026 को भारत में लान्च किया जाएगा। यह फीचर खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत मददगार होगा जो रोजाना फाइलें साझा करते हैं, क्योंकि इसमें लंबा सेटअप या बार-बार डिवाइस कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी।

मोटोरोला के टीडब्ल्यूएस ईयरफोन लान्च

नई दिल्ली। भारतीय बाजार में मोटोरोला ने अपने नए मोटो बड्स 2 प्लस ट्रू वायरलेस स्टीरियो (टीडब्ल्यूएस) ईयरफोन लान्च कर दिए हैं। ये ईयरबड्स पहली बार बार्सिलोना में एमडब्ल्यूसी 2026 में प्रदर्शित किए गए थे। इनमें साउंड बाय बोस के साथ ट्यून किया गया हाइब्रिड डुअल-ड्राइवर सेटअप दिया गया है, जो आडियो अनुभव को एक नया आयाम देता है। इसके अतिरिक्त, मोटो बड्स 2 प्लस एलएचडीसी कोडेक के साथ हाई-रेज आडियो और 55डीबी तक के एडाप्टिव एक्टिव नाइज कैंसिलेशन (एएनसी) को सपोर्ट करते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इनमें ब्लूटूथ 6.0 और डुअल डिवाइस पेयरिंग की सुविधा मिलती है। इन ईयरबड्स की भारत में कीमत 5,999 रुपये तय की गई है और ये पैंटोन कूल व्हाइट व पैंटोन सिलुएट फिनिश में उपलब्ध होंगे। ये आईप54 रेटिंग के साथ धूल और पानी से सुरक्षित भी हैं। मोटोरोला ने इसमें एआई फीचर्स का सपोर्ट भी दिया है, जिसमें कस्टम इक्वलाइजर, फिट टेस्ट और ईयरबड्स को खोजने की सुविधा शामिल है। कम्पैटिबल मोटोरोला डिवाइस पर, ये मोटो एआई टूल्स जैसे कैट मी अप, पे अटेंशन, रिमेंबर दिस और एआई-पावर्ड ट्रांसलेशन का भी समर्थन करते हैं। ग्राहक इन्हें फ्लिपकार्ट पर 8 मई से दोपहर 12 बजे से खरीद सकेंगे।

वैभव को योग्यता के आधार पर आंकना चाहिए, न कि उम्र से

अभी बच्चा है, पर उसकी बल्लेबाजी कमाल की : शिखर धवन

नई दिल्ली

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने राजस्थान रॉयल्स के युवा और तूफानी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के भारत के लिए पदार्पण की संभावनाओं पर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। धवन ने कहा है कि भले ही वैभव की उम्र मात्र 15 साल है, लेकिन जब कोई खिलाड़ी उच्च स्तर पर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहा हो तो उम्र कोई बाधा नहीं रहती। उन्होंने वैभव के निडर रवैये की जमकर सराहना की, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के गेंदबाजों के खिलाफ भी बेखौफ होकर खेलते हैं। धवन ने इस बात पर जोर दिया कि इतनी कम उम्र में ऐसा आत्मविश्वास बहुत कम खिलाड़ियों में देखने को मिलता है, जो वैभव के खेल में साफ झलकता है।

हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में बात करते हुए शिखर धवन ने कहा, अगर वैभव सूर्यवंशी सीनियर लेवल पर लाजवाब प्रदर्शन कर रहा है तो उसे उसकी योग्यता के आधार पर आंकना चाहिए, न कि उसकी उम्र के आधार पर। हां, वह अभी बच्चा है, लेकिन जिस तरह से वह जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह जैसे शीर्ष गेंदबाजों की गेंदों पर इतने बड़े छक्के मारता है, वह वाकई कमाल का है। बहुत से बड़े खिलाड़ी इतनी कम उम्र में वह हासिल नहीं कर पाए जो उसने किया है। जाहिर है, उसका समय आएगा। यह आना ही है। आईपीएल 2025 के बाद से लगातार युवा क्रिकेट और फिर आईपीएल में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से धूम मचा रहे वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में सबसे पहले 400 रनों का आंकड़ा छूने वाले बल्लेबाज बने हैं। उनका स्ट्राइक रेट 238.10 का है, जो किसी भी लीग में असाधारण है। वह अब तक 37 छक्के जड़ चुके हैं, जबकि उनके चौकों की संख्या छक्कों से कम है, जो उनकी आक्रामक खेल शैली को दर्शाता है। इस शानदार प्रदर्शन के बाद से ही हर कोई इस बात की वकालत कर रहा है कि वैभव को जल्द से जल्द भारत की सीनियर टीम में शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि, शिखर धवन का मानना है कि इस युवा प्रतिभा के लिए अभी भारतीय टॉप ऑर्डर में जगह बनाना एक बड़ी चुनौती है।

धवन ने स्वीकार किया कि भारतीय टीम के स्थापित टॉप ऑर्डर में सेंध लगाना वैभव सूर्यवंशी के लिए फिलहाल मुश्किल है। भारत ने हाल ही में 2026 टी20 विश्व कप जीता है और संजू सैमसन व अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ी भी शानदार फॉर्म में हैं, ऐसे में इस युवा खिलाड़ी को आसानी से मौका नहीं मिलेगा। वनडे क्रिकेट में कप्तान शुभमन गिल और रोहित शर्मा ओपनर के तौर पर अपनी जगह मजबूत कर चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट में यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल भी अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। बैकअप ओपनर्स के तौर पर उन्हें टीम के साथ रखा जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी भारत के पास पर्याप्त और अनुभवी विकल्प मौजूद हैं।

न्यूज ब्रीफ

सीन एबॉट ने बयां किया फिलिप ह्यूज की मौत का दर्द

नई दिल्ली। सीन एबॉट अपने दोस्त फिलिप ह्यूज की दर्दनाक मौत को याद कर एक बार फिर भावुक हो गए। यह घटना कई बार उन्हें भावुक कर देती है। क्रिकेट इतिहास के सबसे डरावने और रूह कंपा देने वाले पलों में ऑस्ट्रेलिया के उभरते स्टार फिलिप ह्यूज की दर्दनाक मौत को हमेशा याद किया जाता है, जो 25 नवंबर 2014 को सीन एबॉट के एक बाउंसर के कारण हुई थी। सिडनी में एक घरेलू मैच के दौरान यह घातक घटना घटी, जब एबॉट की गेंद ह्यूज की गर्दन के पास लगी, जिससे उनकी धमनी को चोट पहुंची और दो दिन बाद सेंट विंसेंट अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। इस त्रासदी ने दुनिया भर के खेल प्रेमियों को झकझोर कर रख दिया था। इस घटना का सबसे गहरा असर गेंदबाज सीन एबॉट पर पड़ा था। वे कई महीनों तक ह्यूज की मौत के सदमे में रहे, और उस पल की यादें उनके मन में गहराई तक बस गईं। एबॉट ने उस भयानक पल को याद करते हुए लिखा था कि उन्हें लगा था कि फिलिप ने शॉट खेलने में थोड़ी जल्दी कर दी थी। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है फिलिप ने शॉट खेलने में थोड़ी जल्दी कर दी थी। अगर बल्लेबाज शॉट में जल्दी करता है तो लगता है कि गेंद उतनी तेज नहीं थी जितनी उसने सोची थी। मुझे याद नहीं कि गेंद तेज थी या धीमी।

पाकिस्तान कप्तान ने एशिया कप हैंडशेक विवाद पर खोला राज

नई दिल्ली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने पिछले साल एशिया कप के दौरान भारतीय टीम के साथ हुए हैंडशेक विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने एक पॉडकास्ट में अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि कैसे उनकी टीम मैच खत्म होने के बाद भारतीय ड्रेसिंग रूम तक हाथ मिलाने गई थी, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने ऐसा नहीं किया। सलमान ने याद दिलाया कि एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच कुल तीन भिड़ंत हुईं थीं, और तीनों ही मौकों पर भारतीय टीम ने हाथ मिलाने से परहेज किया। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि टूर्नामेंट से पहले हुए फोटोशूट और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों टीमों के कप्तानों ने निश्चित रूप से हाथ मिलाए थे। पिछले साल संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में खेले गए उस एशिया कप में, सलमान अली आगा की कप्तानी वाली पाकिस्तान टीम को भारत से लगातार तीन हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय खेमे ने यह नीति पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवारों के सम्मान में और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करने के उद्देश्य से अपनाई थी। इस नीति के तहत, टॉस के समय और मैच की समाप्ति के बाद भी दोनों टीमों के खिलाड़ियों और सहायक स्टाफ के बीच कोई हैंडशेक नहीं हुआ था, जिससे यह घटना काफी चर्चा का विषय बनी रही। पॉडकास्ट में विस्तार से बात करते हुए, पाकिस्तान के टी20 कप्तान सलमान अली आगा ने बताया कि टूर्नामेंट से पहले होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्रॉफी फोटोशूट के दौरान तो दोनों टीमों के बीच सामान्य तरीके से हैंडशेक हुआ था। इसी कारण, उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैच के बाद हालात अलग होंगे।

रुतुराज ने कार्तिक, कंबोज और नूर की जमकर प्रशंसा की

चेन्नई। चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ आईपीएल मुकाबले में जीत पर खुशी जतायी है। रुतुराज ने मैच में अच्छे प्रदर्शन के लिए युवा कार्तिक शर्मा की जमकर प्रशंसा की है। रुतुराज ने कहा कि कार्तिक लंबे छक्के लगाने वाला खिलाड़ी है। इससे अलावा उन्होंने तेज गेंदबाज अंशुल कम्बोज और स्पिनर नर अहमद की कसी हुई गेंदबाजी की भी प्रशंसा की है। अंशुल ने 3 जबकि नूर ने 2 विकेट लेकर अपनी टीम की जीत में प्रमुख भूमिका निभाई। इस मैच में जीत के साथ ही सीएसके की प्लेऑफ के लिए संभावनाएं बढ़ी हैं। इस मैच में सीएसके के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मुंबई को 159 रनों पर ही रोक दिया। सीएसके ने कप्तान रुतुराज और कार्तिक के अर्धशतकों की सहायता से 11 गेंदें शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने 159 रन बनाये। सीएसके की ओर से कम्बोज ने तीन विकेट जबकि नूर ने दो विकेट लिए। इन गेंदबाजों के अच्छे प्रदर्शन से मुंबई की टीम बड़ा स्कोर नहीं बना पायी। इसके बाद लक्ष्य का पीछा करते हुए सीएसके की टीम शुरुआत अच्छी नहीं रही। । सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन 11 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह की गेंद पर आउट हुए। इसके बाद उर्विल पटेल ने 12 गेंदों में तेजी से 24 रन बनाए। दो विकेट जल्दी गिरने के बाद कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने युवा बल्लेबाज कार्तिक शर्मा के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया।

आईपीएल के 'बिगड़ैल' खिलाड़ी विवादों से करियर पर पड़ा असर

नई दिल्ली

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग हाल ही में वेपिंग यानी ई-सिगरेट के सेवन को लेकर एक बड़े विवाद में फंस गए हैं। पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में रियान को ड्रेसिंग रूम में ई-सिगरेट पीते हुए देखा गया, जो आईपीएल के नियमों का सीधा उल्लंघन है। इस घटना ने एक बार फिर आईपीएल में खिलाड़ियों के अनुशासन और नियमों के प्रति उनकी जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

बीसीसीआई ने इस मामले पर रियान पराग से जवाब तलब किया है और इस घटना के कारण उन पर प्रतिबंध भी लग सकता है। रियान पराग का यह मामला आईपीएल में ऐसे कई बैड बॉय खिलाड़ियों की याद दिलाता है, जिन्होंने नियमों की धज्जियां उड़ाईं, जिसके कारण किसी का करियर बर्बाद हुआ तो किसी को लंबे समय तक प्रतिबंध झेलना पड़ा।

इस सूची में पहला और सबसे बड़ा विवाद हरभजन सिंह और एस श्रीसंत के बीच हुआ थप्पड़ कांड है। आईपीएल 2008 में किंग्स इलेवन पंजाब और मुंबई इंडियंस के बीच मैच के बाद यह शर्मनाक घटना हुई। मैच हारने के बाद चिढ़े हुए हरभजन सिंह ने श्रीसंत को मैदान पर ही थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद श्रीसंत मैदान पर रोते हुए देखे गए। इस घटना पर बीसीसीआई ने तत्काल सख्त कार्रवाई करते हुए हरभजन सिंह को पूरे आईपीएल सीजन के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। इसके अलावा, उनकी 11 मैचों की मैच फीस भी काट ली गई। हालांकि, बाद में दोनों खिलाड़ियों के बीच सुलह हो गई, लेकिन इस घटना ने आईपीएल के शुरुआती दौर में काफी हंगामा मचाया था।

दूसरा मामला भी एस श्रीसंत से जुड़ा है, लेकिन इस बार उनका नाम स्पॉट फिक्सिंग जैसे गंभीर आरोप में आया। साल 2013 में दिल्ली पुलिस ने राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज श्रीसंत को बुकीज के साथ मिलकर स्पॉट फिक्सिंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। आरोप था कि उन्होंने मैच के दौरान तौलिये से सिग्नल देकर बुकी के कहने पर तय रन दिए थे। इस घटना के बाद बीसीसीआई ने श्रीसंत पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया, जिसने उनके अंतरराष्ट्रीय करियर को पूरी तरह खत्म कर दिया। हालांकि, लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा को कम कर 7 साल कर दिया, लेकिन तब तक उनका सुनहरा करियर समाप्त हो चुका था।

इस लिस्ट में दिग्गज ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा का नाम भी शामिल है। साल 2010 में युवा रवींद्र जडेजा पर आरोप लगा कि वह अपनी मौजूदा टीम राजस्थान रॉयल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने के बजाय दूसरी टीमों के साथ बेहतर डील के लिए सौदेबाजी कर रहे थे। यह आईपीएल के खिलाड़ी नियमों का स्पष्ट उल्लंघन था, जिसके तहत खिलाड़ी अपनी मौजूदा टीम के साथ कॉन्ट्रैक्ट के दौरान अन्य टीमों से बातचीत नहीं कर सकते। इस मामले में आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने जडेजा पर एक साल का प्रतिबंध लगाया था, जिसके कारण वह आईपीएल 2010 में नहीं खेल पाए थे। यह उनके उभरते करियर के लिए एक बड़ा झटका था।

पूर्व क्रिकेटर टीपी सुधींद्रा भी आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग मामले में फंसे थे। साल 2012 में एक न्यूज चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में डेक्कन चार्जर्स के टीपी सुधींद्रा को घरेलू मैचों और आईपीएल में फिक्सिंग के लिए पैसे मांगते हुए पकड़ा गया। स्टिंग ऑपरेशन में उन्होंने यह स्वीकार किया था कि वह पैसों के लिए नो-बॉल फेंक सकते हैं। बीसीसीआई ने आरोपों की पुष्टि होने के बाद टीपी सुधींद्रा पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया, जिससे उनका क्रिकेट करियर हमेशा के लिए समाप्त हो गया। लिस्ट में अजीत चंदीला और अंकित चव्हाण का भी नाम शामिल है। ये दोनों खिलाड़ी साल 2013 के उसी स्पॉट फिक्सिंग कांड में एस श्रीसंत के साथ लिप्त थे। राजस्थान रॉयल्स के अजीत चंदीला और अंकित चव्हाण को भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। चंदीला को बुकीज और खिलाड़ियों के बीच मुख्य कड़ी माना गया था, जबकि अंकित चव्हाण ने कथित तौर पर एक ओवर में तय रन देने की बात मानी थी। इन दोनों खिलाड़ियों पर भी बीसीसीआई ने लाइफ टाइम बैन लगाया था, जिससे उनके भी क्रिकेट करियर पर विराम लग गया। ये सभी घटनाएं आईपीएल में खिलाड़ियों के लिए कड़े अनुशासन और नियमों के पालन की अनिवार्यता को उजागर करती हैं।

इंग्लैंड दौरे के लिए इंडिया-ए महिला टीम का ऐलान, टी20 और वनडे स्क्वॉड घोषित

नई दिल्ली

इंग्लैंड दौरे के लिए भारत की महिला 'ए' टीम का ऐलान कर दिया गया है। चयन समिति ने इंडिया-ए महिला क्रिकेट टीम की टी20 और वनडे दोनों फॉर्मेट के लिए अलग-अलग स्क्वॉड घोषित किए हैं, जो इंग्लैंड-ए महिला टीम के खिलाफ सीरीज खेलेंगे।

टी20 टीम की कमान अनुभवी खिलाड़ी अनुष्का शर्मा को सौंपी गई है, जबकि उपकप्तान की जिम्मेदारी वृंदा दिनेश को दी गई है। टीम में युवा और उभरते खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, जिनमें जी. कमलिनी (विकेटकीपर), उमा चेत्री, वैष्णवी शर्मा, प्रेमा रावत, पूर्वजा वर्लेकर, जिंतिमानी कलिता, सैमा ठाकोर, सिमरन बहादुर, श्वेता सहरावत, दीया यादव, मिन्नू मणि, शबनम शकील और तनुजा कंवर शामिल हैं।

वहीं वनडे टीम की कप्तानी हरलीन देओल को सौंपी गई है, जबकि प्रतिका रावल को उपकप्तान बनाया गया है। इस टीम में प्रिया पुनिया, तनिषा सिंह, जी. कमलिनी (विकेटकीपर), उमा चेत्री (विकेटकीपर), तेजल हसबनीस, निकी प्रसाद, प्रेमा रावत, तनुजा कंवर, वैष्णवी शर्मा, शबनम शकील, सयाली सतघरे, जिंतिमानी कलिता और सैमा ठाकोर जैसे खिलाड़ी शामिल हैं।

इस दौरे को युवा खिलाड़ियों के लिए अहम अवसर माना जा रहा है, जहां वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा साबित कर सकेंगे। चयनकर्ताओं ने संतुलित टीम बनाने की कोशिश की है, जिसमें अनुभव और युवा जोश का अच्छा मिश्रण देखने को मिलता है।

इंग्लैंड की परिस्थितियों में खेलना हमेशा चुनौतीपूर्ण माना जाता है, ऐसे में यह सीरीज खिलाड़ियों के कौशल और मानसिक मजबूती की भी परीक्षा होगी। इस दौरे से कई नई प्रतिभाएं उभरकर सामने आ सकती हैं, जो भविष्य में सीनियर टीम के लिए दावेदारी मजबूत करेंगी।

ग्रेटर नोएडा में 5वीं राष्ट्रीय व्हीलचेयर क्रिकेट चैंपियनशिप का शुभारंभ

ग्रेटर नोएडा। व्हीलचेयर क्रिकेट इंडिया एसोसिएशन (डब्ल्यूसीआईए) की आयोजित 5वीं राष्ट्रीय व्हीलचेयर क्रिकेट चैंपियनशिप 2026 का शुभारंभ हो गया है। ग्रेटर नोएडा स्थित शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मशहूर फिल्म अभिनेता जैकी श्रॉफ ने शनिवार को चैंपियनशिप का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किया। यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट 10 मई तक चलेगा। इसमें पूरे देश की शीर्ष टीमें एक रोमांचक 'सुपर 5' ग्रैंड फाइनल फ़ॉर्मेट मे प्रतिस्पर्धा करेंगी, जो भारत में व्हीलचेयर क्रिकेट के उच्चतम स्तर को प्रदर्शित करेगा। उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए अभिनेता जैकी श्रॉफ ने खिलाड़ियों के जुनून और दृढ़ संकल्प से बेहद प्रभावित होकर एक प्रेरणादायक संदेश साझा किया। उन्होंने कहा कि सभी के लिए मेरा संदेश यह है कि जिंदगी में बिंदास रहो। ये खिलाड़ी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। मैंने इन खिलाड़ियों को देखा और उनके जुनून को देखकर मैं अभिभूत हो गया।

खेल मंत्री मांडविया ने मदिकेरी में उभरते हॉकी खिलाड़ियों से की मुलाकात, बताया – 'भविष्य के ओलंपियन'

मदिकेरी

केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने कर्नाटक के मदिकेरी स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) प्रशिक्षण केंद्र का दौरा कर युवा हॉकी खिलाड़ियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों से प्रतिभाओं को पहचानने और निखारने पर जोर देते हुए भारत को खेल महाशक्ति बनाने की दिशा में इसे अहम बताया।

मांडविया ने विशेष रूप से कोडवा समुदाय की महिला हॉकी खिलाड़ियों से बातचीत की और उनकी प्रतिभा की सराहना की। उन्होंने कहा कि कोडगु जिला भारतीय हॉकी की मजबूत नींव रखने वाले क्षेत्रों में से एक रहा है। इस समुदाय से कई खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और ओलंपिक में भी हिस्सा ले चुके हैं। खेल मंत्री ने कहा कि देश में खेलों के लिए व्यापक और मजबूत ढांचा तैयार किया जा रहा है, जिसमें जमीनी स्तर से प्रतिभाओं को आगे लाना प्राथमिकता है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत के पास प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और सही दिशा में प्रयासों से देश वैश्विक स्तर पर खेलों में मजबूत पहचान बना सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार खेल इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। बड़े खेल आयोजनों की मेजबानी भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। मांडविया ने उम्मीद जताई कि वर्ष 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमें शानदार प्रदर्शन करेंगी। मदिकेरी स्थित साई प्रशिक्षण केंद्र आधुनिक सुविधाओं से लैस है और यहां युवा खिलाड़ियों को उच्च स्तर का प्रशिक्षण दिया जाता है। यह केंद्र देश के विभिन्न राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों के लिए प्रतिभाएं तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मांडविया ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि ये युवा खिलाड़ी भविष्य में भारत का नाम रोशन कर सकते हैं और अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखते हैं

कोच जयवर्धने ने बुमराह, सूर्यकुमार सहित सीनियर खिलाड़ियों का बचाव किया

चेन्नई

आईपीएल के 19 वें सत्र में मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है और उसे लगातार हार झेलने पड़ी है। सीएसके के खिलाफ अहम मैच में भी टीम हार गयी। इससे उसके प्लेऑफ में पहुंचने की राह तकरीब बंद हो गयी है। टीम के खराब प्रदर्शन का कारण स्टार खिलाड़ियों का असफल होना भी रहा है, जिससे वे प्रशंसकों के निशाने पर है हालांकि टीम के मुख्य कोच मेहेला जयवर्धने टीम के शीर्ष खिलाड़ियों का बचाव करते हुए कहा कि टीम की हार के लिए जसप्रीत बुमराह, सूर्यकुमार यादव जैसे स्टार खिलाड़ियों को दोष देना गलत है। साथ ही कहा कि फार्म हासिल करने के लिए इन खिलाड़ियों के लिए एक ही मैच भी पर्याप्त है।

इस सत्र में मुम्बई 9 में से 7 मैच हारकर टीम अंक तालिका में 8वें पायदान पर है। उसे सीएसके के खिलाफ मैच में भी हार झेलनी पड़ी है। इसके बाद से सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं।

प्रशंसक जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों फ्रेंचाइजी अपने शीर्ष खिलाड़ियों बुमराह, सूर्यकुमार और तिलक वर्मा से अच्छा प्रदर्शन नहीं ले पा रही है। इसी को लकर जयवर्धने ने इन खिलाड़ियों का बचाव किया है।

इस सत्र में बुमराह को मुंबई की ओर से नौ मैचों में तीन विकेट मिले हैं। सूर्यकुमार का औसत 20 रन है और तिलक हर मैच में करीब 24 रन बना रहे हैं। इन तीनों खिलाड़ियों के बावजूद मुंबई का अब तक का अभियान अच्छा नहीं रहा है और टीम लगभग प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। जयवर्धने ने अपने शीर्ष खिलाड़ियों को दोष देन से से इंकार कर दिया है। उनका कहना है कि सूर्यकुमार जैसे खिलाड़ी को फॉर्म में लौटने के लिए बस कुछ अच्छी पारियों की जरुरत है।

उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि उनका आउटपुट कम हुआ है। अगर उन्हें कुछ अच्छी पारियां मिल जाएं तो वो फिर से लय में आ जाएंगे। आज भी उन्होंने उस फेज में शानदार बल्लेबाजी की और गेंदबाजों पर दबाव बनाया। अगर वो कुछ ओवर और खेल जाते तो बड़ा स्कोर बना सकते थे। कभी-कभी जब चीजें आपके पक्ष में नहीं होतीं तो सबकुछ हाथ से निकल जाता है। .'

वहीं तिलक को लेकर जयवर्धने ने कहा कि वो अभी भी सीख रहे हैं कि टी20 फॉर्मेट में अपनी बल्लेबाजी को कैसे आगे बढ़ाना है। उनके अलग-अलग परिस्थितियों में खेलने के तरीके को लेकर चिंता जरूर है, लेकिन श्रीलंकाई दिग्गज का मानना है कि अनुभव के साथ सब ठीक हो जाएगा। जयवर्धने ने कहा, 'तिलक भी अभी सीख रहे हैं और उन्हें अलग-अलग भूमिकाएं निभानी पड़ रही हैं। टी20 क्रिकेट इतना आसान नहीं है। जितना ज्यादा वो अलग-अलग हालातों में खेलेंगे, उतना ही समझ पाएंगे कि उन्हें क्या करना है।' वहीं बुमराह का विकेट न लेना भी टीम के लिए नुकसानदायक रहा है। जयवर्धने के अनुसार, ये सिर्फ बुमराह की नहीं, बल्कि पूरी गेंदबाजी इकाई की समस्या है।

पेरैंटहुड से आप कभी रिटायर नहीं होते। पेरैंटहुड जीवन भर का काम है, इसमें कोई पैंशन नहीं होती। जब आपके बच्चे 40 वर्ष के हो जाते हैं और आगे उनके भी बच्चे हो जाते हैं तब भी आपके बच्चे आपकी मृत्यु तक आपके लिए 18 वर्ष के ही रहते हैं। उन्हें हमेशा आपकी स्वीकृति तथा हमदर्दी की जरूरत रहेगी।

बिना शर्त करें बच्चों से प्यार

पूरे घर में शांति का माहौल है। आपके बच्चे कालेज, जॉब्स या विवाह कर चुके हैं। आप आशा करते हैं कि आपके बच्चे खुश होंगे, वे अच्छा कर रहे होंगे और सही राह पर चल रहे होंगे। फिर भी आप बीते समय के माता-पिता नहीं होंगे, पेरैंटहुड से आप कभी रिटायर नहीं होते। पेरैंटहुड जीवन भर का काम है, इसमें कोई पैंशन नहीं होती। जब आपके बच्चे 40 वर्ष के हो जाते हैं और आगे उनके भी बच्चे हो जाते हैं तब भी आपके बच्चे आपकी मृत्यु तक आपके लिए 18 वर्ष के ही रहते हैं। उन्हें हमेशा आपकी स्वीकृति तथा हमदर्दी की जरूरत रहेगी।

बदलती भूमिकाएं

परिवर्तन जीवन का सार है। आप अपनी जॉब पर सर्वाधिक जूनियर से लेकर कंसल्टैंट तक अपनी भूमिका बदल चुके हैं। आपके जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता विकसित, परिवर्तित होता है और आगे बढ़ता है इसलिए भी आपके बच्चों के साथ आपका रिश्ता तब उतार-चढ़ावों से गुजरता है जैसे-जैसे वे कानूनी तौर पर वयस्क होते जाते हैं। 'बिग बॉस' होने के कई वर्ष बाद बच्चों के साथ एक वयस्क रिश्ता रखना मुश्किल होता है।

पीछे की ओर कदम

आपके पास अपने बच्चे के पथ को आलोकित करने वाली मार्गदर्शक रोशनी बनने के लिए 21 से अधिक वर्ष थे। यदि उन्होंने आपके मूल्य-मान्यताओं को नहीं अपनाया है तो अभी से आपको उन्हें बताना होगा कि क्या करना है। आप उनके विकास के वर्षों में उनके रोल मॉडल रहे हैं। अब वक्त उनके पंख फैलाने का, उनकी जिंदगी में किताबें, अनुभव तथा अन्य लोगों को शामिल करने का है। वे क्या सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, कहां से सीखते हैं और किसके साथ सीखते हैं, इसका चुनाव करने के लिए आपको उन्हें उनके पैरों पर खड़े होने देना चाहिए। आपने उन्हें जो सिखाया है उसे व्यवहार में लाने को कहें। यदि आप उनकी ई-मेल्स या फेसबुक अकाऊंट पर नजर रखते हैं, उनकी लेट नाइट पार्टियों के निमंत्रणों और दोस्तों को बहुत निर्दयता से नकार देते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आप उन्हें बता रहे हैं कि वे अपनी खुद की जिंदगी नही चला सकते।

बच्चों से अपेक्षा न करें

जब आप अपने बच्चों से सहायता की अपेक्षा करते हैं तो या तो आप अपने बच्चों से झूठ बोल रहे होते हैं या फिर आप उन्हें भावनात्मक तौर पर ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। इस प्रकार वे दोषी महसूस करते हैं। यह एक ऐसी बात है जो आपको बच्चे के साथ नहीं करनी चाहिए। जैसे-जैसे वे बड़े होते जाते हैं वे बड़ी चीजों के लिए आपकी जरूरत महसूस करेंगे। आपको इस बात पर गर्व होना चाहिए कि संकट के समय आप अपने बच्चे के लिए पहले व्यक्ति हैं जिन्हें वह सहायता के लिए पुकारता है। बच्चों की सहायता करने वाला बनने से भावनात्मक संतोष मिलता है। इसके साथ ही प्यारा, स्वतंत्र तथा जिम्मेदार बच्चा बनाने की प्राप्ति की भावना भी आपके मन में जगती है।

निर्णय लेने में सहायता करें

यदि आपसे किसी बात पर आपका मत पूछा जाए चाहे यह जीवनसाथी के बारे में हो या कॉलेज के किसी कोर्स के बारे में, अपना मत अवश्य दें। उन्हें प्रवचन न दें और न ही उनका मजाक उड़ाएं। आपके बच्चे को इस बात का विश्वास होना चाहिए कि एक संवेदनशील उत्तर के लिए वह आप पर निर्भर कर सकता है।

उनके लिए हमेशा मौजूद रहें

जब आपके बच्चे छोटे थे तो जिस प्रकार आप उन्हें चूमते या दुलारते थे, उस प्यार का प्रदर्शन करना कभी भी बंद न करें। आप हमेशा उनके कंधों पर बांहें रख सकते हैं, उन्हें गले लगा सकते हैं और साधारण शब्दों में उन्हें आई लव यू कह सकते हैं। उनके साथ बिना शर्त प्यार करें। किसी भी प्रकार की उपलब्धि हासिल करने पर अपने बच्चों का स्वागत करें।

...ताकि मेकअप न लगे 'मेडअप'

मेकअप किसी भी महिला का मेकओवर कर उसे खूबसूरत बना सकता है। सही तरीके और कलात्मकता के साथ किया गया मेकअप आपकी लुक्स को और भी निखार देता है और दिन भर आपको प्रैजैंटेबल बनाए रखने में मदद भी करता है।

खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है लेकिन खूबसूरत या प्रैजैंटेबल दिखना आपकी पर्सनैलिटी का प्लस प्वाइंट हो सकता है, बशर्ते कि आपने मेकअप सही तरीके से अप्लाई किया हो। मेकअप करने के लिए चेहरे को तैयार करना बेहद जरूरी है। चेहरे की क्लीजिंग, टोनिंग और माइश्चराइजिंग के बाद चेहरा मेकअप के लिए तैयार होता है।

याद रखें कि ज्यादा माइश्चराइजर लगाने से मेकअप कुछ देर में काला हो जाता है। प्रैक क्रीम चेहरे की कमियों को छुपा कर उसे सुंदर दिखाती है, उसके बाद फाऊंडेशन लगाएं। फाऊंडेशन आपकी स्किन टोन से मेल खाता हुआ या फिर एक टोन ऊपर होना चाहिए। फाऊंडेशन को चेहरे पर अच्छी तरह से ब्लैंड करना चाहिए। कंसीलर लगाने के बाद चेहरे की कोटिंग करें। इसके लिए शैडर का यूज करें। कोटिंग करने से नाक और चीक बोन्स उभर कर दिखती हैं और मेकअप कई गुना सुंदर हो जाता है। चेहरे के मेकअप के बाद आंखों का मेकअप करते समय हमेशा हाईलाइटर यूज करना चाहिए।

आंखों की देखभाल

अगर आपकी आंखों के नीचे काले घेरे अधिक हैं लेकिन आप काजल भी लगाना चाहती हैं तो मायूस न हों। पहले किसी अच्छे कंसीलर का इस्तेमाल कर लें। अगर आपका रंग सांवला है तो लाल रंग के कंटैंट कंसीलर का इस्तेमाल करें। वहीं रंग गोरा है तो पीले कंटैंट वाले कंसीलर का प्रयोग करें। इससे आपके काले

घेरे छुप जाएंगे। अगर आपकी आंखों पर काजल फैल जाता है लेकिन काजल लगाना आपको पसंद है तो बाजार से पाऊडर ब्लैक कलर केक का इस्तेमाल कर सकती हैं। आप कुछ भी कर लें अगर आपकी आंखों पर काजल फैलने की समस्या रहती है तो सिल्वर लाइनिंग का प्रयोग कर सकती हैं। इससे यह फैलेगा नहीं, साथ ही थकी हुई बेजान आंखों में यह नई ताजगी ले आएगा।

लिप्स की देखभाल

- लंबे समय तक लिपस्टिक की चमक बरकरार रखने के लिए लिपस्टिक लगाने के बाद टिश्यू पेपर से एक्सट्रा लिपस्टिक को निकाल दें। इससे लिपस्टिक की चमक पूरा दिन बनी रहेगी।
- डार्क कलर की लिपस्टिक लिप्स को स्माल लुक देती है। अगर आप अपने लिप्स को बड़े साइज का दिखाना चाहती हैं तो नैचुरल कलर यूज करें।
- अगर लिप्स बहुत मोटे हैं तो कंसीलर और फाऊंडेशन की मदद से उन्हें पतली शेप दें। लिप लाइनर से आऊटलाइन ड्रॉ करें और डार्क कलर की लिपस्टिक लगाएं।
- अगर लिप्स को हॉट लुक देना हो तो स्ट्राबेरी और चेरी शेड्स वाली लिपस्टिक भी लगा सकती हैं।

पार्टी मेकअप

पार्टी की जान बनना हो या भीड़ में अलग दिखना हो, इसके लिए मेकअप भी कुछ अलग व अनोखा होना चाहिए। पार्टी चाहे कैसी भी हो, उस में ग्लैमरस दिखने के लिए मेकअप कुछ ऐसा हो जो आप को महफिल की रौनक बना दे। पार्टी में जाने का शौक तो हम सभी को होता है लेकिन कई बार हम यह सोच कर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि किस पार्टी में कैसा मेकअप करें।

जानें कुछ टिप्स

- मेकअप में बेस में शीयर फाऊंडेशन का इस्तेमाल करें। मेकअप ऐसा हो जो शाइनिंग लुक लिए हुए तो हो ही, साथ ही ज्यादा देर तक टिका भी रहे।
- मेकअप में कुछ लोग पेल शेड्स का यूज करने लगते हैं लेकिन ये शेड्स इंडियन स्किन टोन पर सूट नहीं करते। इसलिए लाइट कलर्स से एक शेड डार्क के ऑप्शन पर जाएं। पिंकिश मॉव कलर हर स्किन टोन पर सूट करता है। अगर आप इसे आईशैडो में यूज करती हैं, तो चीक्स पर रोजी ब्लशर लगाएं और लिप्स पर रोज पिंक शेड अप्लाई करें।
- आईलाइनर का इस्तेमाल करते हुए ध्यान रखें कि अब 1960 के दशक के फैशन का चलन दोबारा लौट आया है। इसलिए आईलाइनर आंखों से थोड़ा बाहर निकला हुआ होना चाहिए।
- यदि आप पार्टी के लिए मेकअप कर रही है तो ड्रैस से मैच करता आईशैडो अच्छा लगता है। आईशैडो में मॉव, पिंक, लाइट ब्ल्यू और ग्रीन लाइट शेड्स यूज करें। इसमें लुक पेंटेड नहीं, बल्कि नैचुरल लगती है। आईलाइनर, मस्कारा और काजल आंखों की खूबसूरती बढ़ाता है।
- आईशैडो की आऊटर साइड पर डार्क और इनर कॉर्नर पर लाइट शेड का यूज करें। इसके साथ कलर्ड आईलाइनर का यूज कर सकती हैं। नैचुरल कलर के आईशैडो को कलर्ड आईलाइनर जैसे वॉयलेट, डार्क ब्ल्यू जैसे शेड्स के साथ लगाएं। नैचुरल ग्लो के लिए चीक्स पर लाइट शेड्स के ब्रॉन्जर का यूज कर सकती हैं।
- अगर आपको सैंसुअस दिखना है, तो साड़ी से बेहतर और कोई ड्रैस नहीं है। इसके साथ आप खूबसूरत मैचिंग ज्यूलरी जरूर कैरी करें। मैट फिनिश्ड गोल्ड ज्यूलरी जैसा बैटर आप्शन और कोई नही है।
- होंठों को उभारने के लिए लिप लाइनर, लिपस्टिक और लिप ग्लॉस लगाएं। होंठों को शाइनी लुक देने के लिए उस पर कॉपर रस्ट लिप कलर लगाएं।
- बालों को स्ट्रेट करा के खुला छोड़ दें। यह अपने आप में एक खूबसूरत व मॉडर्न लुक देता है। हेयरस्टाइल में क्रिंपिंग, रोलर व ड्रायर सैटिंग भी करवा सकती हैं। हेयर कट में लेयर्स और रेजर फैशन में हैं।

आफिस मेकअप

आजकल दफ्तरों में भी बेहद अनौपचारिक वेशभूषा तथा वातावरण का चलन है लेकिन फिर भी दफ्तर का एक अनुशासन और प्रोटोकोल होता है। इसलिए यदि आप वर्किंग वूमन हैं तो मेकअप का सही तरीके से अप्लाई किया जाना और भी आवश्यक हो जाता है। दफ्तर में भी यदि आप भड़कीला मेकअप लगा कर चली जाएं तो आप बेहद फूहड़ दिखेंगी। वर्कप्लेस पर मेकअप आपकी पर्सनैलिटी को उभार सकता है यदि आपने इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया हो तो।

जानें कुछ टिप्स

- आपका मेकअप आपके कार्यस्थल के लिहाज से होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि आप कॉर्पोरेट सैक्टर में काम कर रही हैं तो फॉर्मल लुक अपनाएं और लाइफस्टाइल प्रोफैशन के लिए सैमी-फॉर्मल लुक को चुनें। हमेशा नैचुरल लुक को ही तवज्जो दें यानी ब्राइट मेकअप की जगह लाइट मेकअप को अपनाएं।
- आफिस जाने वाली महिलाओं के पास वक्त की कमी होती है, ऐसे में केवल दो मिनट में मेकअप कर आप खूबसूरत लग सकती हैं। चेहरे पर पैनकेक, आंखों में काजल व आईलाइनर और होंठों पर लिप लाइनर व लिपस्टिक लगाने में केवल दो मिनट का समय लगता है।
- दिन के समय आप एकदम हल्का मेकअप रखें और केवल आंखों को हाईलाइट करने पर ध्यान दें। आंखों पर नैचुरल शेड की आईशैडो की परत लगाएं। इससे आपके पूरे चेहरे को चमक मिलेगी। स्किन कॉम्प्लैक्शन से मैच करते हुए ब्लैक या ब्राऊन मस्कारा चुनें। मस्कारा का सिंगल कोट काफी होगा। ढेर सारे काजल और आईलाइनर से बचें क्योंकि इससे आपकी लुक बहुत हैवी हो जाएगी।
- होंठों पर डार्क कलर की लिपस्टिक लगाने से परहेज करें। लिपबाम या क्लियर ग्लॉस लगाएं। अगर आप लिपस्टिक पसंद करती हैं तो नैचुरल शेड्स ही चुनें। सैमी-फॉर्मल प्रोफैशन या ऐसे प्रोफैशन के लिए जहां आपकी पब्लिक डीलिंग हो, आप थोड़े रंगों का प्रयोग कर सकती हैं।

ये भी जान लें

जब सोने जाएं, तो अपना सारा मेकअप उतार दें, वरना स्किन खराब होने का चांस ज्यादा होता है।

मुल्तानी मिट्टी के असाधारण फायदे

- त्वचा के रूखेपन को दूर करने के लिए साबुन की जगह मुल्तानी मिट्टी रगड़ कर स्नान करें। त्वचा कोमल व मुलायम हो जाएगी।
- गर्मी में मुल्तानी मिट्टी मल कर स्नान करने से शीतलता मिलती है।
- गर्मी में पैरों के तलवों में मुल्तानी मिट्टी का लेप करने से ठंडक मिलती है व तलवों की जलन शांत होती है।
- मुल्तानी मिट्टी में कुछ बूंदें सिरके की डाल कर आंखों के नीचे सावधानीपूर्वक लगाएं। काले घेरे धीरे-धीरे समाप्त हो जाएंगे।
- तैलीय त्वचा के लिए मुल्तानी मिट्टी में खीरे का रस, दही व चुटकी भर हल्दी मिक्स करके चेहरे पर पैक की तरह लगाएं। सूखने पर धो दें। लाभ मिलेगा।
- मुल्तानी मिट्टी में संतरे का रस या टमाटर का गूदा मिक्स करके चेहरे पर लगाएं। 10-15 मिनट बाद धो दें। चेहरा खिल उठेगा।
- मुल्तानी मिट्टी में खीरे का रस व आलू का गूदा मिला कर आंखों के नीचे रखें। 10-15 मिनट बाद धो दें। काले घेरों से निजात मिलेगी।

चिपोटले बीन बरीटोज

सामग्री - 1 टेबलस्पून कैनोला ऑयल, 1 तुरीं लहसुन अच्छी तरह पिसी हुई, 1/2 टेबलस्पून चिपोटल मिर्च पाऊडर, 1/4 टेबल स्पून नमक, 1/3 कप पानी, 1 कप आर्गैनिक ब्लैक बीन्स (रैडी टू ईट), 1 कप आर्गैनिक किडनी बीन्स (रैडी टू इर्ट), 3 टेबलस्पून फ्रैश सालसा, 6 (10 इंच की) रिड्यूस फैट टोरटिल्स (रैडीमेड चपाती), 1 कप कटा मैक्सिकन पनीर मिश्रण, 1/2 कप बारीक कटा टमाटर, 1/2 कप ताजा छोटे लेटिस लीव, 6 टेबलस्पून कटा हुआ हरा प्याज, 6 टेबलस्पून लाइट सोर क्रीम

विधि - 1. एक नॉनस्टिक पैन में ऑयल डालकर गर्म करें और उसमें लहसुन डालें तथा एक मिनट तक पकाएं। अब इसमें नमक और चिली पाऊडर डाल कर 3 मिनट तक लगातार हिलाती रहें। अब इसमें 1/3 कप पानी तथा बीन्स डालकर उबालें। आंच कम कर 10 मिनट तक पकने दें। आंच से हटाकर सालसा डालें तथा फोर्क से बींस के मिश्रण को अच्छी तरह मिलाएं। 2. गर्म टोरटिल्ज (पैकिंग पर लिखे अनुसार) पर लगभग 1/3 कप बींस के मिश्रण को मध्य में डालें और फैलाएं। उस पर अढ़ाई चम्मच चीज, 1/4 कप टमाटर, 1/4 कप लैटिस लीव, 1 टेबलस्पून प्याज तथा एक टेबलस्पून सोर क्रीम डालकर रोल करें। बाकी के टोरटिल्ज को भी इसी तरह तैयार करें। इन्हें आप 6 लोगों को सर्व कर सकती हैं।

एरोमैटिक स्लो-रोस्टेड टोमैटोज

सामग्री - 1 टेबलस्पून चीनी, 1 बड़ा चम्मच जैतून का तेल, 1/2 टेबलस्पून नमक, 1/2 टेबलस्पून सूखे तुलसी के पत्ते, 1/2 टेबलस्पून सूखे अजवायन के पत्ते, 1/4 टेबलस्पून ताजा पिसी काली मिर्च। 16 टमाटर मध्यम आकार के (बीच से लम्बाई में कटे हुए) तथा कुकिंग स्प्रे

विधि- 1. ओवन को 200 डिग्री पर प्री-हीट करें, 2. पहले सात इन्ग्रेडिएंट्स एक बड़े बाऊल में डालें। टमाटरों पर सारे मसाले कोट हो जाएं इसलिए उन्हें हल्के हाथ से पलटाएं। एक बेकिंग शीट पर टमाटरों को व्यवस्थित करें। कटी हुई साइड ऊपर रखें। अब कुकिंग स्प्रे करें और इसे आप ओवन में रख दें। रोस्ट होने पर इसे बाहर निकाल लें और सर्विंग डिश में सजा लें। इसे आप 8 लोगों में सर्व कर सकते हैं।

मुद्रक एवं प्रकाशक राकेश शर्मा द्वारा अजय त्यागी के लिए ईको प्रिंटिंग प्रेस, पोस्ट एवं पीएस : गड़चुक, कटाबाड़ी मस्जिद के पास, कामरूप (मेट्रो), गुवाहाटी-35 से मुद्रित एवं **गुड लक पब्लिकेशंस, हाउस नं. 30, डी. नेउग पथ, डोना प्लैनेट के नजदीक, एबीसी, जीएस रोड गुवाहाटी-5 से प्रकाशित।**
संपादक : राकेश शर्मा, मोबाइल : 94350-14771, 97070-14771 ● **कार्यकारी संपादक : प्रदीप शील ● सहयोगी संपादक : रवि शंकर चौधरी ● फोन : 0361-2960054 (संपादकीय)** e-mail : viksitbharatsamacharghy@gmail.com, **(सभी विवाद सिर्फ गुवाहाटी न्याय क्षेत्र के अधीन)**